04 - भूदान आंदोलन के 75 वर्ष : भूमि, न्याय और नैतिकता की पुकार

05 - तस्करी और अपराध के शिकंजे में नौनिहाल

A Daily News Magazine

भोपाल

शनिवार, 18 अप्रैल, 2026

06 - नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत धार जिले में विभिन्न...

07 - विद्यार्थियों को दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 225, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

होर्मुज के बाद अब मलक्का स्ट्रेट को लेकर चिंता क्यों?

लुइस बारूचो

दुनिया के सबसे अहम जलमार्गों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जारी नाकाबंदी के बीच, वैश्विक व्यापार के लिए एक और अहम स्ट्रेट पर अब दुनिया का ध्यान जा रहा है। और यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित जलमार्ग है मलक्का स्ट्रेट। दरअसल, बीते सोमवार को अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये बात सामने आई कि अमेरिका ने इंडोनेशियाई क्षेत्र के ऊपर सैन्य उड़ानों के लिए व्यापक अनुमति का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को लेकर इंडोनेशियाई अधिकारियों ने पुष्टि की है और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पर फ़ैसला अभी लंबित है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का कदम वैश्विक भू-राजनीतिक पर प्रभाव डाल सकता है।

मलक्का स्ट्रेट में घटनाओं पर अध्ययन करने वालीं अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ़ इलिनॉय उर्बाना-शैंपेन में पीएचडी शोधार्थी और क्षेत्रीय विशेषज्ञ अज़ीफ़ा अस्ट्रिना कहती हैं, 'मलक्का स्ट्रेट अहम है क्योंकि यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला सबसे छोटा और सबसे प्रभावी समुद्री मार्ग है, जो मध्य पूर्व, यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच व्यापार के लिए इसे अनिवार्य बनाता है। यह सीधे दक्षिण चीन सागर से जुड़ता है, जिसके रास्ते वैश्विक व्यापार का लगभग एक तिहाई हिस्सा गुजरता है। इसका सबसे संकरा हिस्सा, केवल लगभग 2.8 किलोमीटर चौड़ा है, जो सिंगापुर के पास फिलिप्स चैनल के क़रीब है।

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में हर दिन 23.2 मिलियन बैरल तेल मलक्का से गुजरा, जो वैश्विक समुद्री तेल परिवहन का लगभग 29% है। इसी दरम्यान इस जलमार्ग से रोज़ाना लगभग 260 मिलियन घन मीटर तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भी गुजरी। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीड्स में माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लेक्चरर गोकचे बालची के अनुसार, यह जलमार्ग 'इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता सामान, औद्योगिक उत्पाद, मशीनरी और कारों' के लिए भी एक अहम रास्ता है। दुनिया के कार व्यापार का लगभग 25% इसी रास्ते से गुजरता है। अनाज और सोयाबीन जैसे सूखे थोक माल भी इस स्ट्रेट से गुजरते हैं। होर्मुज़ भी वैश्विक व्यापार के लिए अहम है, लेकिन मलक्का जितना बड़ा ट्रांस-शिपमेंट केंद्र नहीं है। इसकी भूमिका ऊर्जा से आगे बढ़कर कई तरह के सामानों के परिवहन तक फैली है। मलक्का वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रमुख धमनियों में से एक है। '

समुद्री डकैती एक लगातार बनी रहने वाली चिंता है। सिंगापुर स्थित रीकैप इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर के अनुसार, 2025 में मलक्का और सिंगापुर स्ट्रेट में समुद्री लूट की 108 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2007 के बाद सबसे अधिक हैं। यह स्ट्रेट प्राकृतिक ख़तरों से भी संवेदनशील है, जिनमें सुनामी और ज्वालामुखी गतिविधियां शामिल हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि मलक्का की भू-राजनीतिक संवेदनशीलता भी बहुत अधिक है।

इस इलाक़े के समुद्री क्षेत्र में दबदबे को लेकर चीन, अमेरिका या भारत के बीच किसी भी तरह का तनाव बढ़ना, इस स्ट्रेट से गुजरने वाले मार्ग को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अस्ट्रिना का कहना है कि इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य पहुंच बढ़ने की संभावना के भी दीर्घकालिक असर हो सकते हैं, 'मैं इसे संरचनात्मक रूप से अस्थिर करने वाला मानूंगी, भले ही यह तुरंत व्यापार को प्रभावित न करे। जब अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति अपनी गतिविधियां बढ़ाती है, तो यह सुरक्षा व्यवस्था में एक ऐसा आयाम जोड़ देती है जिसे संभालने के लिए यह सिस्टम तैयार नहीं है। चिंता दीर्घकालिक तनाव बढ़ने को लेकर है। अगर चीन इसे एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते के पास अमेरिकी निगरानी या रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के रूप में देखता है, तो वह प्रतिक्रिया दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि व्यापार को बाधित करे बल्कि अपनी मौजूदगी या प्रभाव बढ़ाकर। उनके अनुसार, आप एक सहयोगी, क़ानून लागू करने वाली केंद्रित सुरक्षा व्यवस्था से सैन्य रूप से अधिक होड़ वाले माहौल की ओर धीरे-धीरे बदलाव देख सकते हैं। आस्ट्रिना कहती हैं कि वैश्विक व्यापार के लिए असर बहुत सीधे नहीं दिखेगा, लेकिन बीमा प्रीमियम बढ़ सकते हैं, जोखिम की भावना बढ़ सकती है और उस रास्ते पर अस्थिरता बढ़ सकती है जिस पर वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत अधिक निर्भर है। इसे इस तरह नहीं देखना चाहिए कि इंडोनेशिया किसी एक पक्ष के साथ खड़ा हो रहा है। इंडोनेशिया संतुलन की रणनीति अपनाता दिख रहा है, वह अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ा रहा है, साथ ही चीन के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाए रखा है और रूस जैसे अन्य साझेदारों से भी जुड़ा है। बड़ी तस्वीर गठबंधन बनाने की नहीं है, बल्कि यह है कि बड़ी शक्तियों की होड़ अब उस क्षेत्र में एंट्री ले रही है, जिसे ऐतिहासिक रूप से वैश्विक व्यापार के लिए साझे रूप से संचालित किया जाता रहा है।'

साल 2003 में, तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ ने 'मलक्का डायलेमा' यानी 'मलक्का दुविधा' शब्द गढ़ा था, जोकि चीन की इस जलमार्ग पर भारी निर्भरता को दिखाता है। बालची कहते हैं, सिर्फ़ चीन ही नहीं। जापान और दक्षिण कोरिया भी ऊर्जा के लिए इस स्ट्रेट पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जहां उनके लगभग 90% तेल आयात इसी रास्ते से आते हैं। यह जलमार्ग सिंगापुर के लिए भी बेहद अहम है, जहां दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह है और यह जहाज़ों के ईंधन भरने का बड़ा केंद्र भी है। अस्ट्रिना कहती हैं कि चीन के लिए निकट भविष्य में इस स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता कम करना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में चीन के पास इस निर्भरता को किसी तरीक़े से कम करने का कोई वास्तविक विकल्प है। चाहे पाइपलाइन हों या अन्य गलियारे, वैकल्पिक मार्ग कुछ हद तक मददगार हो सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर मलक्का की जगह नहीं ले सकते। बालची इस बात से सहमत हैं, 'दो सबसे व्यवहारिक विकल्प, सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट, भी इंडोनेशिया के जलक्षेत्र में ही हैं।'

पापुआ न्यू गिनी के पास टोरेस स्ट्रेट 'एक उथला और संवेदनशील जलमार्ग है, जहां कोरल लीफ़ हैं और बड़े कमर्शियल जहाज़ यहां से नहीं गुजर सकते। बालची कहते हैं कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के रास्ते घूमकर जाना 'बहुत अधिक लागत और समय' लेगा। जबकि अस्ट्रिना कहती हैं कि इन सीमाओं को देखते हुए चीन का ध्यान अपनी कमज़ोरी को ख़त्म करने के बजाय उसे मैनेज करने पर है। यह दुविधा निर्भरता कम करने के बारे में नहीं है। यह इस बात पर है कि चीन इस निर्भरता को कैसे मैनेज करता है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

वो और मोहब्बत से मुझे देख रहा हो
क्या दिल का भरोसा मुझे धोका ही हुआ हो

होगा कोई इस दिल सा भी दीवाना कि जिस ने
ख़ुद आग लगाई हो बुझाने भी चला हो

इक नींद का झोंका शब-ए-ग़म आ तो गया था
अब वो तिरे दामन की हवा हो कि सबा हो

दिल है कि तिरी याद से ख़ाली नहीं रहता
शायद ही कभी मैं ने तुझे याद किया हो

'जेब' आज है बे-कैफ़ सा क्यूँ चाँद न जाने
जैसे कोई टूटा हुआ पैमाना पड़ा हो।

- जेब गोरी

अमेरिकी डॉलर को छोड़ चीन की करेंसी युआन में किया पेमेंट

ईरान से तेल खरीद पर भारत का 'बड़ा खेल'

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रिफाइनर कंपनियों ने ईरान से खरीदे गए तेल का भुगतान चीनी मुद्रा युआन में किया है। यह पेमेंट ऐसे समय हुआ है जब ईरानी तेल खरीदने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों में अस्थायी छूट मिली है। रॉयटर्स के मुताबिक यह पेमेंट मुंबई स्थित बैंक के जरिए किया गया, जिसने अपनी शंघाई शाखा के माध्यम से रकम ट्रांसफर की। भारतीय रिफाइनर्स ने सात साल बाद ईरान से तेल खरीदा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इसका पेमेंट मोड है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इस महीने की शुरुआत में 20 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल खरीदा।

यह तेल बड़े जहाज जया के माध्यम से आया। यह करीब 20 करोड़ डॉलर (करीब 1857 करोड़ रुपये) का सौदा था और पिछले सात वर्षों में भारत की पहली ईरानी तेल खरीद मानी जा रही है। अलावा निजी क्षेत्र की रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी चार जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर आने की अनुमति दी गई थी।

अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी रूस से तेल खरीद रहा भारत

- अधिकारी ने कहा-किसी पर निर्भर नहीं भारत, खुद तय करता है नीति

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका ने हाल ही में रूसी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों को एक बार फिर लागू कर दिया है। इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की मिली छूट खत्म हो गई है। हालांकि भारत इसके बाद भी रूस से कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद जारी रखेगा। भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने साफ कहा है कि भारत की ऊर्जा आयात नीति पूरी तरह उसका अपना फैसला है और यह अमेरिकी प्रतिबंधों पर निर्भर नहीं है। मिंट ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि भले ही अमेरिका ने इस छूट को आगे नहीं बढ़ाया है।

ईरान की तरफ से थीं पेमेंट की अनोखी शर्त

आमतौर पर भारतीय सरकारी कंपनियां तेल की डिलीवरी मिलने के बाद भुगतान करती हैं। लेकिन इस सौदे में कई शर्तें शामिल रहीं। ये इस प्रकार हैं: कंपनी ने तेल की कुल कीमत का 95 फीसदी हिस्सा तभी चुका दिया जब टैंकर भारतीय समुद्री सीमा में दाखिल हुआ। जानकारों के मुताबिक, प्रतिबंधों वाले देशों के साथ इस तरह की भुगतान व्यवस्था काफी असामान्य है। सूत्रों के अनुसार इंडियन ऑयल फिलहाल ईरान से और तेल खरीदने की योजना नहीं बना रही है। साल 2019 के बाद से भारत ने अमेरिकी दबाव के चलते ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। अब तक चीन की छोटी और स्वतंत्र रिफाइनरियां ही ईरानी तेल की मुख्य खरीदार रही हैं। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि यह छूट अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और ईरानी तेल पर प्रतिबंधों की छूट रविवार को समाप्त हो जाएगी।

लोकसभा में नहीं पास हो सका महिला आरक्षण बिल

- विपक्ष ने नहीं दिया साथ, पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े

नई दिल्ली (एजेंसी)। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान संशोधन बिल संसद में गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 489 सांसदों ने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 489 का दो तिहाई 326 होता है। इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया। 11 साल के शासन में यह पहला मौका जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। इससे पहले अमित शाह ने एक घंटा स्पीच दी थी। कहा था कि अगर ये बिल पास नहीं होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। विपक्ष अगर वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा। देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन है। सरकार ने कहा है कि इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने सांसदों के बीच ड्राफ्ट बिल बांटे। ये बिल महिलाओं के लिए आरक्षण कानून 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लागू करने और नए सिरे से परिसीमन करने से जुड़े हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया, भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया।

2023 का महिला आरक्षण हो गया कानून लागू

आधी रात को नोटिफिकेशन जारी, विपक्ष हमलावर

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून यानी 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है। संसद में गुरुवार से ही इसके संशोधन पर 3 दिनों के लिए बहस शुरू हुई। इस बीच, आधी रात को मूल कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसका मतलब यह है कि महिला आरक्षण के जिस कानून में संशोधन की बात की जा रही है, वह लागू ही नहीं हुआ था। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, कानून में संशोधन तभी हो सकता है जब वह लागू हो चुका हो। अचानक सरकारी नोटिफिकेशन की यही वजह है।

सरकार के पास क्या विकल्प बचेंगे

मोदी सरकार लोकसभा में बिल पर वोटिंग करा सकती है, अगर बिल गिर जाता है, तो सरकार इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ सकती है। विपक्ष के साथ आम सहमति बना सकती है। विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति के पास भेज सकती है। सरकार इससे पहले वन नेशन,वक्फ बिल और वन इलेक्शन बिल को भी संसदीय समिति के भेज चुकी है। केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू बोले- सरकार ने महिला आरक्षण कानून में बदलाव (संशोधन) करने की तैयारी कर रही है।

2023 में कानून बना लेकिन लागू नहीं हुआ था

महिला आरक्षण बिल को 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी लेकिन इसके बावजूद यह कानून संविधान का हिस्सा नहीं बना था। क्योंकि कोई कानून तब तक लागू नहीं माना जाता जब तक सरकार राजपत्र (गजट) में उसको लागू करने की तारीख अधिसूचित न कर दे। अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कानून तो लागू हो गया है लेकिन इसे मौजूदा लोकसभा में लागू नहीं किया जा सकता। कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, अगली जनगणना और उसके आधार पर परिसीमन (सीटों का पुनर्गठन) होगा। इसके बाद ही आरक्षण लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के कारण आरक्षण 2034 तक लागू होने की संभावना जताई गई थी। हालांकि, सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर महिला आरक्षण को 2029 के चुनाव से लागू करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने संसद में तीन नए बिल पेश किए हैं- संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, 2026।

मप्र की धरती ने ऐतिहासिक रूप से किया आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार

आदि शंकराचार्य का दर्शन भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक एकता का बना आधार : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अद्वैत ज्ञान के सूर्योदय के केन्द्र ओंकारेश्वर की चेतना की अनुभूति आज सबको हो रही है। ज्ञान और ध्यान की धरती मध्यप्रदेश ने ऐतिहासिक रूप से धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया है। हर युग में इसके प्रमाण विद्यमान हैं। श्रीरामचन्द्र जी वनवास मिलने पर मंदाकिनी माता के किनारे चित्रकूट के धाम पधारें और प्रभु श्रीराम का आगे का जीवन मानव मात्र के लिए पूजनीय हो गया, समाज ने रामराज्य का अनुभव प्राप्त किया। भगवान श्रीराम ने संस्कारों, व्यवहारगत मूल्यों, परस्पर संबंधों सहित शासन के ऐसे सूत्र प्रदान किए जो आज भी महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार श्रीकृष्ण, कंस वध के बाद शिक्षा ग्रहण करने उज्जयिनी स्थित सांदीपनि आश्रम पधारें। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने कर्मवाद का संदेश दिया, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। सनातन काल में कालड़ी केरल से चले 8 वर्षीय बालक शंकर ओंकारेश्वर पधारे, जहां परम पूज्य गुरू गोविंदपाद जी के आशीर्वाद से आदि शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म की धारा को अविरल रूप से बहाने का आधार प्रदान किया। आदि शंकराचार्य का दर्शन भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक एकता का आधार बना। हमारी सनातन विरासत, शास्त्र और आध्यात्मिक परम्पराएं यदि आज जीवित एवं जागृत हैं तो यह आदिगुरू शंकराचार्य के प्रयास और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आचार्य शंकराचार्य जी की जयंती के अवसर पर ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में आयोजित 5 दिवसीय प्रकटोत्सव के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में श्री द्वारका शारदा पीठ के जगदगुरू शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती, विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्ष पद्मश्री निवेदिता भिड़े, स्वामी शारदानंद सरस्वती सहित वरिष्ठ संतवृंद उपस्थित थे।

एकात्म यात्रा तथा अद्वैत पर आधारित लघु फिल्मों का हुआ प्रदर्शन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज के साथ वैशाख शुक्ल पंचमी के उपलक्ष में आयोजित आदि शंकराचार्य के प्रकटोत्सव 'एकात्म पर्व' कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अद्वैत लोक एवं अक्षर ब्रह्म प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। साथ ही वे वैदिक अनुष्ठान में भी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्कृत सेवा फाउंडेशन पुणे के श्री रोहन अच्युत कुलकर्णी द्वारा लिखित पुस्तक 'वेदांतसिद्धान्तचन्द्रिका विथ उदग्र' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एकात्म धाम की यात्रा, प्रकल्प और भावी स्वरूप पर केंद्रित वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में एकात्म यात्रा तथा अद्वैत पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया।

पं.दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत में होती है एकात्मता के भाव की अभिव्यक्ति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार सनातन संस्कृति के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित है। चिंतक एवं विचारक पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में भी एकात्मता के भाव की अभिव्यक्ति होती है। राज्य सरकार अंत्योदय के सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उदारमना भारतीय सनातन संस्कृति में भक्षण को नहीं अपितु दूसरों के कल्याण को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। पंच दिवसीय एकात्म पर्व में पधारे संत, मनीषी, विद्ववान एकात्मकता के वैश्विक संदेश को रेखांकित करेंगे। यह पर्व आधुनिक समाज और नई पीढ़ी को अद्वैत से जोड़ने का अभिनव और सफल प्रयास सिद्ध होगा।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 18 अप्रैल 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

टीएमसी विधायक के ठिकानों पर आईटी का छापा

● ममता बोलीं-भाजपा चाहे जितनी साजिश रच ले, उसकी हार होगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुक्रवार को आयकर विभाग ने टीएमसी विधायक देबाशीष कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने सुबह करीब 6 बजे मणोहरपुकुर रोड स्थित उनके घर और ऑफिस पर तलाशी की। देबाशीष कुमार दक्षिण कोलकाता की राशबेहारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कई बार तलब किया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार की सभा में कहा- हमारे पार्टी कार्यालयों, कैंडीडेट के घरों तक पर छापेमारी हो रही है लेकिन, चाहे कितनी भी साजिश रच लें, भाजपा को हार का सामना करना ही होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार की सभा में कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक में कहा है कि उत्तर बंगाल में विकास विभाग में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं कहती हूं, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। हालांकि यह पद आपके लिए लंबे समय तक नहीं रहेगा। जब तक आप यहां हैं, कृपया कम झूठ बोलें।

बालाकोट, नोटबंदी, सिंदूर का जादूगर पकड़ा गया

● संसद में बोले राहुल गांधी, बिना नाम लिए पीएम मोदी पर साधा निशाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा, 'यह महिला आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएगा। यह शर्मनाक कानून है, पुराना कानून लाओ हम समर्थन देंगे। यह सिर्फ भारत के निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे को बदलने के लिए है।' उन्होंने कहा,भारत के इतिहास में यह सबसे कड़वा सच है। मैं इसके बारे में सब

जानता हूं। यह ओबीसी, दलित वर्गों के लिए क्रूरता वाला बिल है। सभी जानते हैं कि ओबीसी, दलित और महिलाओं के साथ क्या होता है। सरकार ओबीसी का अधिकार छीनना चाहती है। राहुल ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा- ऑपरेशन सिंदूर-नोटबंदी का जादूगर पकड़ा गया। इस पर एनडीए सांसदों ने विरोध किया। बोले- राहुल प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उनके विवादित शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया।

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोला कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे

● ट्रम्प बोले-शुक्रिया,भारत ने ईरान से 2,358 लोगों को निकाला

तेल अवीव/तेहरान (एजेंसी)। ईरान ने सीजफायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। यह फैसला लेबनान में सीजफायर के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि जहाज एक सुरक्षित रास्ते से गुजरेंगे, जिसे ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से तय कर रखा है, ताकि सफर के दौरान कोई खतरा न हो। अराघची ने कहा कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित न हो। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को शुक्रिया कहा है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुल गया है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने अब तक ईरान से 2,358 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है।

आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते हैं, कानून से नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन की सुनवाई जारी रही। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट राजीव धवन ने कोर्ट से कहा कि आस्था या विश्वास समय के साथ हमेशा बदलते रहते हैं। यह बदलाव सिर्फ किसी कानून के बन जाने से नहीं आता; बल्कि यह बदलाव तो लोगों के बीच से ही उभरकर आता है। इससे पहले 9 जजों की बेंच ने 15 अप्रैल की सुनवाई में कहा था कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। साथ ही यह भी कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। वहीं मंदिर प्रशासन त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने कहा कि सबरीमाला कोई खिलौने की दुकान या रेस्टोरेंट

याचिकाकर्ता बोला-सबरीमाला केस में 5वें दिन भी हुई सुनवाई

का मामला नहीं है। यहां के देवता ब्रह्मचारी हैं। भारत में अयप्पा के लगभग 1,000 मंदिर हैं। अगर महिलाओं को दर्शन करना है, तो वहां जाएं। उन्हें इसी खास मंदिर में क्यों आना है। केरल हाईकोर्ट ने 1991 में सबरीमाला में मासिक धर्म वाली महिलाओं (10-50 साल) की एंट्री पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बैन हटा दिया। फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गईं, जिसपर अब सुनवाई हो रही है। मंदिर प्रशासन महिलाओं की एंट्री का विरोध कर रहा है। सबरीमाला मंदिर मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू हुई है। पहले 3 दिन, 9 अप्रैल तक सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं की एंट्री के विरोध में दलीलें रखीं। सरकार ने कहा था कि देश के कई देवी मंदिरों में पुरुषों की एंट्री भी बैन है, इसलिए धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

दोस्त को धमकाया...समझाने गया तो सीने में मार दी गोली

6 आरोपियों पर केस दर्ज, मुख्य आरोपी भी घायल, दोनों पक्षों में पहले से था विवाद

देवास (नप्र)। देवास के भवानी सागर क्षेत्र में गुरुवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान आरोपियों ने एक कार में भी तोड़फोड़ की। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। वहीं, दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति भी जिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने मामले में छह नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

दोस्त के फोन पर समझाने गया था- जानकारी के अनुसार, लड्डू उर्फ शुभम पिता महेश नाथ गुरुवार रात घर पर भोजन कर रहा था। इसी दौरान उसके दोस्त गौतम (23) का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि कुछ लोग उसे

रोककर विवाद कर रहे हैं। इसके बाद लड्डू रात 1 बजे मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव करने लगा, लेकिन इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते विवाद बढ़ गया। विवाद के दौरान दो आरोपियों ने पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली लड्डू के सीने में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गौतम के पैर में गोली लगी। आरोपियों ने इसके बाद हथियारों से मारपीट भी की। परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लड्डू को मृत घोषित कर दिया, जबकि गौतम को इंदौर रेफर किया गया।

परिजनों का आरोप—अब भी मिल रही धमकियां

मृतक के भाई पीयूष ने आरोप लगाया कि घटना के बाद कुछ लोग अस्पताल पहुंचे और धमकी दी कि एक को मार दिया, दूसरे को भी देख लेंगे। परिजनों ने सुरक्षा की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है।

पहले से दोनों पक्षों में विवाद

नाहर दरवाजा थाना प्रभारी अमित सोलंकी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा था। लड्डू टेकरी क्षेत्र में नारियल-प्रसाद और फोटो की दुकान चलाता था। परिजनों का आरोप है कि आरोपी उससे वसूली की मांग करते थे और पहले भी उसकी बाइक जला चुके थे। वहीं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मृतक और घायल पर भी आरोपियों के खिलाफ पहले मामले दर्ज रहे हैं।

मुख्य आरोपी भी अस्पताल में भर्ती

थाना नाहर दरवाजा प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि मुख्य आरोपी वरुण बाली समेत रितिक सिहोते, तुषार सिहोते, मट्टू सिहोते, राहुल शूटर, विपिन बाली सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें इंदौर सहित अन्य स्थानों पर रवाना की गई हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी वरुण शुक्रवार सुबह घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हुआ है।

ढहाई गई संभल मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार

अब बुलडोजर से बाकी हिस्सों को तोड़ रहा प्रशासन

संभल (एजेंसी)। संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे गिरा दी गई। अब बुलडोजर मस्जिद के बाकी हिस्सों को तोड़ रहा है। इससे पहले, सुबह साढ़े 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मस्जिद के बाहर की पांच दुकानों को तोड़ा गया। मस्जिद की मीनार तोड़ने के लिए प्रशासन ने दो हाइड्रा मशीनें बुलाईं। एक मजदूर मीनार पर चढ़कर रस्सी को बांधा, फिर उसके दूसरे सिरे को दोनों हाइड्रा मशीनों से बांधा। इसके बाद मशीनों से खींचकर मीनार को गिरा दिया। मामला मुबारकपुर बंद गांव का है। प्रशासन के मुताबिक, 15 साल पहले सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। फिलहाल, डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी केके बिश्नोई समेत 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर हैं। गांव वाले जुटने लगे तो विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। 12 दिन पहले, यानी 5 अप्रैल को मस्जिद पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन उस समय बुलडोजर चालक ने मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार तोड़ने से मना कर दिया था। तर्क दिया था कि मीनार बुलडोजर के ऊपर गिर सकती है। हालांकि उस दिन मदरसा, पांच दुकानें और मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया था। दुकानों का करीब 20 फीसदी हिस्सा बच गया था, जिसे आज गिराया गया।

मुकेश अंबानी को पछाड़ आगे निकले गौतम अडाणी

● एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, नेटवर्थ 8.59 लाख करोड़ पहुंची

नई दिल्ली (एजेंसी)। अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में उनकी नेटवर्थ 92.6 अरब डॉलर यानी करीब 8.59 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स थे। उनकी नेटवर्थ 90.8 अरब डॉलर यानी करीब 8.42 लाख करोड़ है। गौतम अडाणी: इस साल इनकी नेटवर्थ में 8.1 अरब डॉलर यानी 75.11 हजार करोड़ रुपए बढ़ी है। अडाणी ग्रुप के शेयरों में आई तेजी ने इनकी नेटवर्थ को बूस्ट दिया है।

इलॉन मस्क दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में इलॉन मस्क 656 अरब डॉलर यानी करीब 60 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। उनके बाद लैरी पेज दूसरे और जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि कोई भी भारतीय टॉप टेन में शामिल नहीं है। यह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ को ट्रैक करने वाला एक डेली इंडेक्स है। इसमें न्यूयॉर्क में हर कारोबारी दिन की समाप्ति पर आंकड़े अपडेट किए जाते हैं।

शिक्षक भर्ती, अभ्यर्थियों को CM हाउस घेरने से रोका

भोपाल में बसों में भरकर थाने ले गई पुलिस ; बोले- गालियां दीं, बदसलूकी की, उंगलियां फैक्चर

भोपाल (नप्र)। भोपाल में मप्र शिक्षक भर्ती 2025 के अभ्यर्थी सीएम हाउस घेरने निकले। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर रोक दिया। भीड़ को खदेड़कर भगाया। बस में भरकर खजूरी थाने ले गए। अभ्यर्थियों ने कहा- पुलिस ने गालियां दीं। बदसलूकी की। झड़प में एक अभ्यर्थी के घायल हो गया। उंगलियां फैक्चर हो गईं।

अभ्यर्थियों का कहना है कि- वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने के लिए सीएम हाउस की ओर जा रहे थे। पुलिस ने कुछ देर तक बैठाए रखा। इसके बाद अचानक उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया।

अभ्यर्थियों का आरोप- गाली-गलौज और बदसलूकी- ग्वालियर से आए अभ्यर्थी सूरत सिंह धाकड़ ने बताया कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें वहां से हटाया। हमें खदेड़कर गाड़ियों में बैठाया गया और थाने छोड़ दिया गया, हमारे साथ बदतमीजी की गई।

वहीं, शिवपुरी से आए अभ्यर्थी नितिन ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनकी उंगली फैक्चर हो गई। उन्होंने कहा, हम सिर्फ अपनी मांग रखने जा रहे थे, कोई अपराध नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया।

अभ्यर्थियों के साथ धक्का-मुक्की की गई- प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें जबरन बसों में बैठाया और अलग-अलग जगहों से उठाकर थाने पहुंचाया गया। इस कार्रवाई के दौरान कई अभ्यर्थियों के साथ धक्का-मुक्की और बल प्रयोग के आरोप भी सामने आए हैं।

1.15 लाख पद खाली, फिर भी भर्ती सीमित- अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में 1.15 लाख से अधिक शिक्षक पद खाली हैं, इसके बावजूद भर्ती में सीमित पद घोषित किए गए हैं। इससे योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से भोपाल में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।उन्होंने अपनी मांगों को लेकर खून से आवेदन लिखने, भूख हड़ताल, मुंडन और मार्कशीट दहन जैसे कदम भी उठाए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

ये हैं अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें

- वर्ग-2 (माध्यमिक शिक्षक) भर्ती में प्रत्येक विषय में कम से कम 3,000 पद या कुल मिलाकर न्यूनतम 10,000 पद बढ़ाए जाएं।
- वर्ग-3 (प्राथमिक शिक्षक) भर्ती 2025 में पद संख्या बढ़ाकर कम से कम 25,000 की जाए।
- प्राथमिक भर्ती में शामिल 3,200 विशेष शिक्षक पदों को अलग कर अलग से भर्ती निकाली जाए।

भगवाधारी योगी कर रहे मौलाना और माफिया का जिक्र

पश्चिम बंगाल चुनाव में दोहराएंगे बिहार वाला करिश्मा!

बोलपुर (एजेंसी)। बंगाल में एक बार बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी तो टीएमसी के गुंडे, माफिया और मौलाना झाड़ू लगाते नजर आएंगे। यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है और मस्जिदों से अब शोर-शराबा नहीं होता। यूपी से बुल्डोजर मंगवा लो, गुंडों के इलाज का बस यही जरिया बचा है। ये बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे यूपी के सीएम आदित्यनाथ का अंदाज है, जिसे वह अक्सर रैलियों में बोलते हैं। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में लोग योगी शैली की हिंदी में भाषण समझते कम हैं, मगर जब बुल्डोजर, मौलाना, नमाज और राम मंदिर जैसे शब्द

बोलते हैं तो तालियां बजती हैं। वह भीड़ से हाथ उठाकर जय श्री राम बोलने की अपील करते हैं और जनता वैसा ही करती है। सूत्र बताते हैं कि ब्रांड योगी के करिश्मे के कारण पार्टी ने प्रदेश में 20 से ज्यादा रैली कराने की प्लानिंग की है।

योगी को देखने के लिए उमड़ती है भीड़

योगी आदित्यनाथ सिर्फ भगवा वस्त्र पहनते हैं। ग्रामीण बंगाल में उनके भाषण सुनने से ज्यादा देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। जब वह मंच पर होते हैं तो जनता हाथ जोड़कर अभिवादन करती है। सभा में बीजेपी के झंडे के साथ हनुमान ध्वजा भी होती है। 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की कांथी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जब वह अपनी तीसरी जनसभा में पहुंचे तो बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने दंडवत होकर प्रणाम किया।

जनता की नब्ज टटोलते हैं योगी आदित्यनाथ

पूर्वी मेदिनीपुर के एक सार्वजनिक सभा में योगी ने कहा कि आज बंगाल में जिस तरह की अराजकता, गुंडागर्दी, लूटपाट, तुष्टीकरण और दंगे हो रहे हैं, वैसे ही हालात 2017 से पहले यूपी में भी थे। आज यूपी में न कोई कर्फ्यू है, न कोई दंगा। आज यूपी में सब चंगा है। एक भाषण में उन्होंने कहा कि बंगाल में उर्दू नहीं, बल्कि बांग्ला भाषा ही बोली जाएगी। जिसे उर्दू बोलनी है, वे वहां चला जाए जहां उर्दू बोली जाती है। अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हुए वह खुले तौर से कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी को चुनौती देते हैं।

तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हरिवंश नारायण

● पहली बार मनोनीत सदस्य को पद मिला,पीएम बोले-सदन को उन पर गहरा भरोसा है

नई दिल्ली (एजेंसी)। हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। उन्हें शुक्रवार को निर्विरोध चुना गया हैं। विपक्ष की ओर से कोई नाम नहीं आया था। पहली बार किसी मनोनीत सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। हरिवंश के समर्थन में राज्यसभा सचिवालय को पांच प्रस्ताव मिले।

18 मार्च को पीएम मोदी ने कमबैक का हिंट दिया था

बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान राज्यसभा में रिटायर हो रहे सांसदों का विदाई समारोह 18 मार्च को हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी ने हरिवंश के लिए कहा था-हमारे उपसभापति हरिवंश विदा ले रहे हैं। हरिवंश को इस सदन में लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर मिला। पीएम मोदी ने हिंट दी थी कि हरिवंश की राजनैतिक पारी अभी खत्म नहीं हुई है, वे आगे भी जनहित में काम करते रहेंगे।

शिवराज सिंह चौहान से मिलने दिल्ली पहुंचे धार-खरगोन के किसान

अमानक बीज मामले में हुई कार्रवाई, नुन्हेम्स कंपनी पर एफआईआर दर्ज

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने अमानक बीज को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिल्ली जाकर मुलाकात की है। किसानों से बात के बाद अमानक बीज के मामले में शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया है। साथ ही अमानक बीज बनाने वाली नुन्हेम्स कंपनी पर एफआईआर दर्ज करवाई है। साथ ही आधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए।

शिवराज के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज- मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद मामले में तेज कार्रवाई हुई और धार जिले के मनावर थाने में संबंधित कंपनी नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि किसानों के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं।

करेला के मिले थे अमानक बीज- दरअसल, मध्यप्रदेश के धार और खरगोन के किसानों ने नई दिल्ली में उनसे भेंट कर करेला फसल में अमानक बीज और रोपे के कारण हुए गंभीर नुकसान की जानकारी दी। इसके बाद चौहान ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को साफ कहा कि प्रभावित किसानों को न्याय मिलना चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिस कंपनी की भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

धार में दर्ज हुई है एफआईर- इन निर्देशों के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज हुई और मनावर थाना, जिला धार में एफआईआर क्रमांक 266 दर्ज की गई। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 318(4) और 324(5), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराएं 3 व 7 तथा बीज अधिनियम, 1966 की धारा 19 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। प्राथमिकी में नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है।

सही से नहीं हुआ है करेला का उत्पादन

किसानों की शिकायत है कि उन्होंने नवंबर 2025 में विभिन्न नर्सरियों और कृषि सेवा केंद्रों से संबंधित इस कंपनी के बीज और रोपे खरीदे थे, लेकिन बुआई और रोपण के बाद करेला फसल में अपेक्षित उत्पादन नहीं हुआ और फल छोटे, पीले होकर गिरने लगे। फसल उत्पादन में आई भारी गिरावट के बाद किसानों ने 17 फरवरी 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्ट्या यह पाया गया कि अमानक बीज एवं अमानक बीज से तैयार रोपे किसानों को प्रमाणित बताकर बेचे गए, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा।

किसानों के भरोसे, मेहनत और पूंजी का नुकसान हुआ : शिवराज

यह मामला केवल फसल खराब होने का नहीं, बल्कि किसानों के भरोसे, मेहनत और पूंजी को नुकसान पहुंचाने का है। मैंने करेला के अमानक बीज रूबासटा किस्म प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान बार-बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों की मेहनत, फसल और भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी कई कंपनियों के खिलाफ अमानक बीज के मामले में कार्रवाई की गई है।

मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा कदम, हर कॉलेज में काउंसलर जरूरी

भोपाल (नप्र)। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में जारी इन निर्देशों के अंतर्गत अब सभी शैक्षणिक संस्थानों में काउंसलर की नियुक्ति के साथ कई अन्य व्यवस्थाएं भी अनिवार्य कर दी गई हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, जिन संस्थानों में 100 या उससे अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, वहां कम से कम एक प्रशिक्षित काउंसलर की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। कम छात्र संख्या वाले संस्थानों को बाहरी विशेषज्ञों से जुडकर काउंसलिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। काउंसलर के रूप में मनोविज्ञान में स्नातकोतर, प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्य विशेषज्ञ या संबंधित क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति नियुक्त किए जा सकेंगे।

संस्थान में केवल काउंसलर नियुक्ति पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि पूरे संस्थान को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सभी शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों, प्रशासनिक स्टॉफ और सुरक्षा कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन प्रशिक्षणों में मानसिक स्वास्थ्य, प्राथमिक सहायता, विद्यार्थी के व्यवहार में आए परिवर्तनों की पहचान तथा जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने जैसे विषय शामिल होंगे। साथ ही विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ने पर जोर दिया गया है। संस्थानों को निर्देश दिए गए है कि वे अभिभावकों के लिए नियमित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे वे अपने बच्चों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों को समझ सके और समय रहते उचित सहयोग प्रदान कर सकें।

विद्यार्थियों की व्यक्तिगत निगरानी और मार्गदर्शन के लिए 25 से 40 छात्रों पर एक मैंटर नियुक्त किया जाएगा। यह मेंटर विद्यार्थियों की उपस्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन, व्यवहार और मानसिक स्थिति पर नजर रखेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर परामर्श और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। साथ ही अभिआवकों से संपर्क बनाए रखते हुए विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहयोग करेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी संस्थानों को निर्देशित किया है कि इन व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करते हुए निर्धारित प्रारूप में जानकारी विभाग को शीघ्र प्रेषित करें।

मॅटोर-मॅटी (गार्जियन ट्यूटर) व्यवस्था

प्रत्येक संस्थान द्वारा 25-40 वि?द्यार्थियों पर एक मेंटर की नियुक्ती की जाएगी। यह दायित्व किसी प्राध्यापक को दिया जाएगा, जिसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होगा। मेंटर विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम और व्यवहार की निगरानी और कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उनका मार्गदर्शन करेंगे। मानसिक तनाव व व्यक्तिगत समस्याओं में सहयोग करना। अभिभावकों से नियमित संपर्क बनाए रखना। कैरियर मार्गदर्शन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये प्रेरित करना। सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाना। विद्यार्थियों के रिकॉर्ड व काउंसलिंग रजिस्टर का संधारण करना होगा। संस्थाओं में प्रदर्शित से होंगे हेल्पलाइन नंबर परिसर में प्रमुख स्थानों पर वॉल पेटिंग से हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे।

भोपाल के बड़ा तालाब पर 347 अवैध कब्जे, हटे सिर्फ 50

रसूखदारों के कब्जों पर कार्रवाई नहीं हुई ; तालाब की हद में बने आलिशान घर

भोपाल (नप्र)। भोपाल की लाइफ लाइन बड़ा तालाब के दायरे में आ रहे कुल 347 कब्जों को हटाने में प्रशासनिक अमले की बड़ी लापरवाही सामने आई हैं। ये कब्जे बड़ा तालाब के शहरी हिस्से में FTL यानी, फुल टैंक लेवल से 50 मीटर के दायरे में है। अब तक करीब 50 कब्जे ही हट सकते हैं, जबकि कई रसूखदारों और सरकारी कब्जों पर कार्रवाई नहीं की गई।

बता दें कि बड़ा तालाब पर अतिक्रमण की सारी हदें पार हो चुकी है। अतिक्रमणकारियों ने इसे चारों ओर से अतिक्रमण में जकड़ रखा है। सरकारी रिपोर्ट में ये सामने आ चुके हैं, पर कार्रवाई जमीन पर न होकर फाइलों में ही

सिमटी रही। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्राइबल) की फटकार के बाद मार्च में अतिक्रमण लिस्टेड किए गए। कुल 347 अतिक्रमण या कब्जे सामने आए। इनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही जमीनों के कब्जे शामिल हैं। सर्वे के बाद तत्कालीन कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर 15 दिन की टाइम लाइन तय की गई। जिसमें 6 से 21 अप्रैल तक अलग-अलग क्षेत्र में कार्रवाई करना तय हुआ। बकायदा टीमें बना दी गईं। पुलिस और नगर निगम से को-ऑर्डिनेशन भी हो गया, लेकिन 15 अप्रैल से कार्रवाई थम गईं। वहीं, अब तक जो कार्रवाई हुई, उनमें बड़े कब्जे छोड़ दिए गए। भोपाल के नए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने एक दिन पहले गुरुवार को मीडिया से चर्चा में कहा था कि भोज वेटलैंड राजधानी भोपाल की शान है। हमारी जो भी भूमिका है, उसे बेहतर करेंगे। अच्छा काम आगे बढ़ाएंगे और चुनौतियों को दूर करेंगे।

4 दिन में ये हुई कार्रवाई

6 अप्रैल से कार्रवाई करना तय हुआ था। इस दिन भदभदा की झुग्गियों और दुकानों को हटाया गया। 10 अप्रैल को तहसीलदार हर्षविक्रम सिंह की टीम ने हलालपुरा स्थित तालाब किनारे पर कार्रवाई की। एक मैरिज गार्डन के आगे एक फार्म हाउस पर कर्रवाई की गई। हलालपुरा बस स्टैंड गुलशन गार्डन के पीछे अवैध रूप से बने 25 टीन के शेड व पक्के कमरे, बाउंड्रीवॉल और करबला क्षेत्र में अवैध रूप से बनी टीन की शटर वाली 6 दुकानों को भी जेसीबी के माध्यम से तोड़ा। 13 अप्रैल को सेवनिया गोंड और गौरागांव में कार्रवाई करते कुछ कब्जों की बाउंड्रीवॉल तोड़ दी गई।

'बार-बार बेहोश कर लाना ठीक नहीं'

कूनो से भागकर राजस्थान जा रहे चीते, एक्सपर्ट ने चेताया

श्योपुर (नप्र)। कूनो नेशनल पार्क की सीमा को लांघकर चीते बार-बार राजस्थान जा रहे हैं। 2026 में तीसरी बार कूनो से निकलकर एक चीता राजस्थान पहुंच गया। गुरुवार को वह चीता रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाकों में पहुंच गया। इससे पहले चीता बारां के रास्ते राजस्थान पहुंचा था। इस बार करोटा और फिर सवाई मधोपुर होते हुए वहां पहुंचा है। इससे पता चलता है कि राजस्थान के बड़े इलाके में चीते घूम रहे हैं।

27 मार्च को वापस लाया गया था कूनो- दरअसल, इससे पहले राजस्थान गए चीते को 27 मार्च को ट्रैंकुलाइज कर कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। वह 19 मार्च को राजस्थान गया था। वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि छठी बार कूनो जंगल से

चीता राजस्थान गया है। कूनो और गांधी सागर का बड़ा इलाका मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 1700 वर्गकिलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें बारां, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले शामिल हैं।

सुधीर गुप्ता, पर्यावरणविद् ने कहा केपी-2 को दो बार बेहोश किया जा चुका है। इससे जानवर को नुकसान पहुंच सकता है। अगर चीते स्वाभाविक रूप से राजस्थान में फैल रहे हैं तो उन्हें वहीं रहने देने के लिए एक नीति होनी चाहिए।

तत्काल रणनीति बनाने की आवश्यकता- वहीं, एक अन्य विशेषज्ञ बनवारी यदुवंशी ने कहा कि लंबी दूरी तक जाना चीतों का एक स्वाभाविक क्षेत्रीय व्यवहार है। प्रोजेक्ट चीता एक्शन प्लान में राज्यों के बीच आवाजाही का प्रावधान है। सवाल यह है कि हम उन्हें कब तक वापस धकेलते रहेंगे। राज्यों के बीच एक औपचारिक समझौता और एक संयुक्त रणनीति की आवश्यकता है।

वन विभाग की टीम कर रही है निगरानी

गुरुवार की सुबह पालीघाट के पास अजीतपुरा गांव में केपी-2 चीते को देखा गया। वह गांव की सड़कों पर चलता दिखा है। इसके बाद पास के खेतों में चला गया। वन विभाग की टीम ने सुबह पांच बजे से निगरानी शुरू कर दी थी।

बारीकी से रख रहे हैं लोकेशन पर नजर

वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हम चीते की लोकेशन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। वह इन इलाकों में काफी सहज नजर आ रहा है। केपी-2 बुधवार की रात चंबल नदी को पार करके कोटा जिले में चला गया था। अंधेरे का फायदा उठाकर वापस लौट आया और सुबह होते-होते सवाई माधोपुर में दाखिल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर ट्रैकिंग टीम वहां मौजूद है।

अन्य चीते भी जा रहे हैं राजस्थान

वहीं, केपी-2 अकेला ऐसा चीता नहीं है जो इस इलाके में घूम रहा है। एक और चीता केपी-2 को भी बारां जीला में देखा गया है। वह अटरू और छबड़ा में घूम रहा था। इससे पहले मादा चीता ज्वाला 130 किलोमीटर का सफर तय करके सवाई माधोपुर के बालेर गांव तक पहुंच गई थी, जहां उसने बकरी का शिकार किया था।

गोताखोरों की मदद से 825 किलो का जखीरा बरामद

मैहर पुलिस ने नदी से निकाला अवैध लाहन

मैहर (नप्र)। मैहर जिले की ताला थाना पुलिस ने मुरझुआ नदी से अवैध महुआ लाहन का एक बड़ा जखीरा गुरुवार को बरामद किया है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने गोताखोरों की मदद से नदी के गहरे पानी में छिपाए गए 825 किलोग्राम लाहन को निकालकर नष्ट कर दिया। इसकी अनुमानित कीमत 50 हजार रुपए बताई जा रही है।

ताला थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चौकी मुकुंदपुर क्षेत्र से निकलने वाली मुरझुआ नदी में अवैध शराब बनाने की तैयारी चल रही है। तस्करों ने मरघट घाट से कस्तरा घाट के बीच महुआ लाहन से भरे प्लास्टिक के 55 डिब्बों को पत्थरों से बांधकर 3 से 4 फीट गहरे पानी में छिपा रखा था, ताकि किसी को शक न हो।

सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक नागेश्वर मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस और वन विभाग की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने स्थानीय गोताखोरों की सहायता ली और नदी के पानी में उतरकर गहन तलाशी अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद पानी के भीतर से सभी 55 प्लास्टिक के डिब्बे बाहर निकाले गए।

आरोपी मौके से फरार- इन डिब्बों में कुल 825 किलोग्राम महुआ लाहन भरा हुआ था। पुलिस ने अवैध शराब निर्माण की इस साजिश को विफल करते हुए मौके पर ही पूरे लाहन को नष्ट कर दिया। हालांकि, पुलिस की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस अब उनकी पहचान के लिए आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच जारी है।

बीजेपी नेता ने थार से किया 'तांडव'

पूर्व सरपंच के कार को मारी बार-बार टक्कर, दो की मौत, गिरफ्तार

खंडवा (नप्र)। शिवपुरी के बाद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भी बीजेपी नेता पर थार से तांडव का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने अपनी थार से पूर्व सरपंच की बलेनो कार में तीन बार टक्कर मारी है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही बीजेपी नेता लवकुश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

केनूद के पास घटी है घटना- दरअसल, खंडवा के केनूद के पास सड़क हादसे में मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं, एक युवती और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए है। सभी बलेनो कार में सवार थे। तभी तेज रफ्तार थार ने गाड़ी को कई बार टक्कर मार दी है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट गया है। लोगों का कहना है कि यह हादसा नहीं साजिश है। आरोप सनावद के बीजेपी नेता लवकुश पर लगे हैं।

परिवार का यह है आरोप- वहीं, परिवार के सदस्य ने बताया कि परिवार की बेटी सारी की शादी ठीकरी में तय हुई थी। पांच मई को उसकी शादी थी। लवकुश बहन के पीछे पड़ा था। पहले वह घर आकर धमकाया था। कहा था कि दूसरी जगह शादी नहीं होने दूंगा। मूंदी थाने में इसकी शिकायत भी हुई थी। सभी लोग कार में बैठकर थाने ही जा रहे थे। उसमें सारिका भी थी। केनूद रोड पर पहुंचे तो लवकुश सामने से कार लेकर आया और टक्कर मार दी। फिर भाग गया।

आरोपी लवकुश को हिरासत में लिया- पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्ट्म के लिए भेज दिया है। इसके बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि थार वाहन का चालक सनावद निवासी और भाजपा से जुड़ा नेता लवकुश है। हादसे की खबर मिलते ही अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और आरोपी के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए आरोपी लवकुश को हिरासत में ले लिया है।

मूंदी की ओर जा रहे थे सभी लोग

वहीं, बलेनो कार में सवार सौरभ अपनी मां सुमन बाई, भाई-बहन और साले के साथ मूंदी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही थार कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सौरभ और उनकी मां सुमन बाई की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में कार में सवार सारिका, रविंद्र राठौर और रवि गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक कुसुम सुमन बाई पूर्व सरपंच रही हैं।

कांग्रेस हर विधानसभा में 30 हजार परिवारों से लेगी 100-100 रुपए

कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और संगठन पर खर्च होंगे ; हरीश चौधरी बोले- प्रस्ताव दिल्ली भेजा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के रविंद्र भवन में शुक्रवार को कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह (राहुल), कमलेश्वर पटेल, कांतिलाल भूरिया, डॉ. गोविंद सिंह, विजयलक्ष्मी साधौ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं।

कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बताया कि पार्टी में यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक परिवार से 100 रुपए का सहयोग लिया जाए। यह राशि जिला और ब्लॉक स्तर पर ही खर्च होगी और इसे प्रदेश या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि इस योजना से जुटाए गए संसाधनों का उपयोग प्रशिक्षण और संगठन निर्माण में किया जाएगा, जिससे पार्टी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेगी। कार्यकर्ता ही संसाधन जुटाकर संगठन को मजबूत करेंगे और इससे परिवारों के साथ पार्टी का जुड़ाव भी बढ़ेगा।

जिला अध्यक्षों के काम का मूल्यांकन जारी- चौधरी ने ब्लॉक अध्यक्षों से कहा कि वे मंडल, ब्लॉक, गांव और वार्ड स्तर पर संगठन का गठन सुनिश्चित करें। साथ ही गांवों में जाकर इकाइयों और बीएलए-2 का सत्यापन कर उनकी स्थिति का मूल्यांकन करें। उन्होंने बताया कि जिला अध्यक्षों के काम का मूल्यांकन जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्षों के कार्य का भी छह महीने बाद आकलन किया जाएगा।

पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि पहले भी इस पर सवाल उठे, लेकिन महिलाओं ने अवसर मिलने पर बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं, राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोधिया ने अपने संबोधन में कहा कि जब वे माइक पकड़ते हैं तो मंत्री और मुख्यमंत्री भी घबरा जाते हैं।

संपादकीय

भारतः जीडीपी की गिरती रैंकिंग

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की घटती रैंकिंग अस्थायी भले हो, लेकिन देश की आर्थिकी के लिए चेतावनी जरूर है। इसका मोदी सरकार को कुछ राजनीतिक नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि सरकार ने भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, इसको लेकर बहुत ढोल बजाए थे। लेकिन डॉलर के मुकाबले रूपए के घटते मूल्य ने हमे सीधे चौथे से छठे स्थान पर पहुंचा दिया है। संतोष की बात इतनी है कि ने भारत की आर्थिक विकास की रफ्तार को कम नहीं आंका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2026 के 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' के आंकड़ों के अनुसार, भारत जीडीपी रैंकिंग में 4थे स्थान से फिसलकर छठे पायदान पर आ गया है।

इस गिरावट के प्रमुख कारण और तथ्य इस प्रकार हैं:

आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3.92 ट्रिलियन (अनुमानित) रहा, जिससे ब्रिटेन (4 ट्रिलियन डॉलर) और जापान (4.44 ट्रिलियन डॉलर) उससे आगे निकल गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जीडीपी में यह गिरावट मुख्यतः सांख्यिकीय है, न कि आर्थिक सुस्ती। इसके पीछे मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कमजोरी, डॉलर की मजबूती और आधार वर्ष में संशोधन प्रमुख कारण हैं। भारत के लिए संतोष का विषय यह है कि जीडीपी रैंकिंग गिरने के बावजूद, भारत 6.5% से 7.6% की विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। ऐसे में भविष्य का अनुमान है कि कि भारत 2027 तक 4था स्थान और 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान फिर से हासिल कर सकता है। संक्षेप में कहें तो रुपया कमजोर होने से डॉलर के टर्म में हमारी इकॉनमी का साइज छोटा दिखा है, लेकिन वास्तविक विकास अभी भी मजबूत है। हालांकि कुछ लोग इसे डेटा में हेराफेरी भी मान रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ के अनुमानों के मुताबिक, भारत की जीडीपी 2025 में लगभग 3.92 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो 2024 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर थी। यह मजबूत घरेलू मांग और निरंतर आर्थिक गति के समर्थन से मजबूत नाममात्र वृद्धि को दर्शाता है। गौरतलब है कि आईएमएफ अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में रैंक करता है, जिसका अर्थ है कि स्थानीय मुद्रा जीडीपी को प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके परिवर्तित किया जाना चाहिए। इससे वैश्विक रैंकिंग निर्धारित करने में मुद्रा की गति एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। पिछले एक वर्ष में, भारतीय रुपया 2024 में लगभग 84.6 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर से गिरकर 2025 में लगभग 88.5 रुपये प्रति डॉलर हो गया है, और इसमें और अधिक कमजोरी आने की उम्मीद है। इस बदलाव का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक भारत के जीडीपी के आधार वर्ष और कार्यप्रणाली में संशोधन है। इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक उत्पादन अनुमानों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 के लिए नाममात्र जीडीपी को पुरानी श्रृंखला के तहत 357 ट्रिलियन रुपये से घटाकर नई श्रृंखला में 345.5 ट्रिलियन रुपये कर दिया गया है। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉलर मूल्यों पर आधारित वैश्विक रैंकिंग अक्सर किसी अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित ताकत को छिपा सकती है। हालांकि आगामी वर्षों में रैंकिंग में भारत की स्थिति सुधर सकती है। देश के 2026 में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो अभी भी ब्रिटेन के अनुमानित 4.26 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा कम है।

भूदान आंदोलन के 75 वर्ष : भूमि, न्याय और नैतिकता की पुकार

इक्कीसवीं सदी के किसी भी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, स्थानीय, यहां तक कि मोहल्ले-पड़ौस के आपसी द्वंद्वों को देखें तो उनकी बुनियाद में भूमि के वितरण, विभाजन दिखाई देते हैं। ऐसे में साढ़े सात दशक पहले विनोबा भावे की अगुआई में हुए भूदान, ग्रामदान की अहमियत को समझना प्रासंगिक नहीं होगा? प्रस्तुत है, 'भूदान दिवस' पर इसी की पडताल करता यह विशेष लेख।

नजरिया

कुमार सिद्धार्थ
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

देश के सामाजिक और नैतिक इतिहास में ऐसे कुछ आंदोलन हुए हैं, जिन्होंने बिना हिंसा, बिना सत्ता और बिना संसाधनों के भी समाज की आत्मा को झकझोर दिया है। आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन ऐसा ही एक अद्वितीय प्रयोग था, जिसने न केवल भूमि के पुनर्वितरण का प्रश्न उठाया, बल्कि समाज के नैतिक पुनर्निर्माण की दिशा भी दिखाई। 18 अप्रैल को मनाया जाने वाला 'भूदान दिवस' उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है, जब 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब, जब इस आंदोलन के लगभग 75 वर्ष पूर्ण होने को हैं, इसके महत्व और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर पुनर्विचार आवश्यक हो जाता है।

भूदान आंदोलन की शुरुआत एक साधारण, लेकिन गहरे सामाजिक प्रश्न से हुई थी - क्या समाज अपने ही भूमिहीन लोगों के लिए स्वेच्छा से संसाधन साझा कर सकता है? पोचमपल्ली में जब भूमिहीन परिवारों ने विनोबा भावे से भूमि की मांग की, तब एक जमींदार द्वारा स्वेच्छा से भूमि-दान की घोषणा ने इस आंदोलन को जन्म दिया। विनोबा भावे ने इसे केवल भूमि-दान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे 'सर्वोदय' याने सभी के उत्थान के व्यापक दर्शन से जोड़ा।

भूदान आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाने के लिए विनोबा भावे ने व्यापक पदयात्राएँ कीं, जो इस आंदोलन की आत्मा बन गईं। उन्होंने लगभग 13 वर्षों (1951 से 1964 के बीच) लगातार देशभर में पदयात्रा की और करीब 58,000 से अधिक किलोमीटर पैदल चलकर देश के लगभग 16 से अधिक राज्यों का भ्रमण किया और हजारों गाँवों में पहुँचकर सीधे लोगों से संवाद किया। इन पदयात्राओं के माध्यम से उन्होंने न केवल भूमि-दान का आह्वान किया, बल्कि समाज में समानता, सहयोग और अहिंसक परिवर्तन की भावना को भी गहराई से स्थापित किया। आगे चलकर यह आंदोलन 'ग्रामदान' की अवधारणा तक विस्तारित हुआ, जिसमें पूरे गाँव की भूमि को सामूहिक स्वामित्व और उपयोग के लिए समर्पित करने का विचार सामने आया।

विनोबा मानते थे कि भूमि प्रकृति की देन है और उस पर किसी एक व्यक्ति का पूर्ण स्वामित्व नैतिक रूप से उचित नहीं हो सकता। इसी कारण उन्होंने समाज के संपन्न वर्ग से अपील की कि वे अपनी भूमि का एक हिस्सा भूमिहीनों को दें, ताकि समाज में

संतुलन और समानता स्थापित हो सके। विनोबा के विचार में यह केवल आर्थिक सुधार का उपाय नहीं, बल्कि 'हृदय परिवर्तन' की प्रक्रिया थी, जिसमें दान देने वाला और प्राप्त करने वाला, दोनों एक नए सामाजिक संबंध में जुड़ते हैं। उनका यह भी विश्वास था कि यदि परिवर्तन स्वेच्छा और अहिंसा के आधार पर होगा, तो वह अधिक स्थायी और मानवीय होगा।

भूदान आंदोलन के दौरान प्राप्त जमीनों के वितरण के लिए विभिन्न राज्यों में 'भूदान-यज्ञ बोर्डों' की स्थापना की गई जो दान में प्राप्त भूमि का अभिलेखीकरण, सत्यापन और वितरण सुनिश्चित करते थे। बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्यों में लंबे समय तक 'भूदान-यज्ञ बोर्ड' सक्रिय रहे। इनकी जिम्मेदारी थी कि वे दान की गई भूमि का कानूनी हस्तांतरण कर उसे भूमिहीन परिवारों तक पहुँचाएं। कुछ राज्यों में इन 'बोर्डों' ने उल्लेखनीय कार्य किए, जहां हजारों परिवारों को भूमि का स्वामित्व मिला। हालांकि, कई स्थानों पर इन 'बोर्डों' को प्रशासनिक जटिलताओं, सीमित संसाधनों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई राज्यों में 'भूदान बोर्डों' के पास भूमि का रिकॉर्ड तो था, लेकिन उसका वास्तविक वितरण नहीं हो सका। कुछ स्थानों पर तो भूमि पर कब्जा दिलाने में भी कठिनाइयाँ आईं। इसके बावजूद, यह संस्थागत प्रयास इस बात का प्रमाण है कि भूदान आंदोलन केवल नैतिक अपील तक सीमित नहीं था, बल्कि उसे प्रशासनिक ढांचे में ढालने की भी कोशिश की गई।

वर्तमान समय में भूमि असमानता का प्रश्न नए रूप में सामने आ रहा है। एक ओर बड़े कॉरपोरेट और उद्योग समूह विशाल भूमि पर अधिकार रखते हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों किसान और आदिवासी समुदाय भूमि से वंचित या विस्थापन के खतरे में हैं। शहरीकरण और औद्योगीकरण के बढ़ते दबाव ने भूमि को केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि एक 'वस्तु' में बदल दिया है, जिसका मूल्य बाजार तय करता है, जिससे सामाजिक असमानता और गहरी होती जा रही है।

ऐसे में भूदान आंदोलन याद दिलाता है कि भूमि केवल आर्थिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह जीवन, संस्कृति और अस्तित्व का आधार है। विनोबा भावे का दृष्टिकोण सिखाता है कि विकास का मॉडल केवल आर्थिक लाभ पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सामाजिक न्याय और नैतिकता का भी समावेश होना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि भूदान की भावना को समकालीन संदर्भ में पुनर्परिभाषित किया जाए। यह जरूरी नहीं कि लोग अपनी भूमि दान करें, लेकिन यह आवश्यक है कि समाज और सरकार मिलकर ऐसी नीतियाँ बनाएं, जो भूमि के न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करें। भूमि सुधार, वन अधिकार कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और विस्थापित समुदायों के पुनर्वास जैसे मुद्दे इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

इसके अलावा, भूदान आंदोलन हमें सामुदायिक भावना और साझेदारी की संस्कृति को पुनर्जीवित करने की प्रेरणा भी देता है। आज जब समाज तेजी से व्यक्तिवादी होता जा रहा है, तब 'साझा संसाधन' और 'साझी जिम्मेदारी' की अवधारणा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्राम स्तर पर सामूहिक निर्णय, संसाधनों का साझा उपयोग और स्थानीय स्वशासन की मजबूत व्यवस्था आदि सभी पहलू भूदान के मूल विचार से जुड़े हुए हैं। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से भी भूदान की भावना को आगे बढ़ाया जा सकता है। नई पीढ़ी को यह समझाना जरूरी है कि सामाजिक परिवर्तन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हरेक नागरिक की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। यदि समाज के सक्षम वर्ग स्वेच्छा से कमजोर वर्गों के लिए आगे आएँ, तो असमानता को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

'भूदान आंदोलन' के 75 वर्षों की यात्रा केवल अतीत को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का भी समय है। यदि हम विनोबा भावे के विचारों को आज के संदर्भ में समझकर उन्हें व्यवहार में लाने का प्रयास करें, तो यह आंदोलन एक बार फिर समाज में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर सकता है। 'भूदान दिवस' पर यह संकल्प लेना सार्थक होगा कि हम अपने-अपने स्तर पर समानता, न्याय और साझेदारी की भावना को मजबूत करें। यही इस ऐतिहासिक आंदोलन और उसके प्रणेता विनोबा भावे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। (सप्रेस)

विकास और सुशासन के मुद्दों पर भी काम करे मीडिया

राजनीति

प्रो.संजय द्विवेदी
लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विवि, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं।

मीडिया की ताकत आज सर्वव्यापी है और कई मायनों में सर्वग्रासी भी। ऐसे में विकास के सवालों और उसके लोकव्यापीकरण में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो उठी है। यह एक ऐसा समय है, जबकि विकास और सुशासन के सवालों पर हमारी राजनीति में बात होने लगी है, तब मीडिया में यह चर्चाएं न हों यह संभव नहीं है। समाज विकास की प्रक्रिया और उसकी आकांक्षाएं मीडिया में दर्ज हों, ऐसी उम्मीद की जाती है। इन विषयों की रिपोर्टिंग के लिए तमाम पत्रकार आगे आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी विकास की पत्रकारिता को एक नई नजर से देखा जा रहा है। भारत में विकास की पत्रकारिता और उसके सवालों से जूझने के लिए पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी तैयार है, किंतु मुख्यधारा के मीडिया के द्वारा इन विषयों को तरजीह न दिए जाने के कारण निराशा ही हाथ लगती है। संकट पत्रकारों की ओर से नहीं, मीडिया संस्थानों और प्रबंधकों की ओर से है। विकास का मुद्दा क्या सिर्फ सरकारी विज्ञापनों का विषय है, सरकारी मीडिया का विषय है, या यह समाज में हो रहे नवाचारों का भी विषय है। विकास पत्रकारिता को पाठ्यक्रम के साथ मीडिया कर्म का भी हिस्सा होना चाहिए।

भारत जैसे विविधता और बहुलता भरे समाज में सभी उम्मीदों, सपनों और बदलावों को रेखांकित कर पाना कठिन है। क्योंकि विकास के अनेक तल हैं और देश में समाज की रचना भी बहुस्तरीय है, देश में कहावत प्रचलित है 'चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर वाणी', इसलिए किसी राज्य को भी एक ही पैमाने से नहीं नापा जा सकता। जैसे मध्य प्रदेश में एक तरफ समृद्ध मालवा है, तो दूसरी और झाबुआ जैसे इलाके भी हैं। एक तरफ इंदौर की चमक है, तो दूसरी ओर अलीराजपुर जैसे क्षेत्र भी हैं। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ है, तो भिलाई भी है। ऐसे में पत्रकारों या विकास के सवालों पर लिखने वालों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसी तरह विकास की भूमिका भी यहां विस्तृत और परिवर्तित हो जाती है। हम देखें तो 1950 के पहले आर्थिक विकास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। किंतु 1950 के बाद की चिंताएं अलग हो गयी। बाद के दिनों में सामाजिक विकास को एक बड़ा कारक माना जाने लगा है। सामाजिक न्याय से लेकर स्थाई विकास के सवाल अब बड़े हो गए हैं। यहां तक कि पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें भी हमारे सामने हैं।

एक समय में विकसित और विकासशील देशों की बहसें भी हमने सुनीं जिनमें मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट एक अलग तरह से बात करती हुयी नजर आती है, जिनमें कुछ सवाल आज भी मौजू हैं। नियंत्रित मीडिया से मीडिया के चौतरफा विकास का समय भी आया जिसमें कुछ भी छिपाना और दबाना असंभव सा हो गया। कई बार यह भी लगता रहा कि विकास का सवाल सिर्फ सरकारी माध्यमों (मीडिया) के लिए ही महत्व का है, बाकी माध्यमों का अपना एजेंडा और राय अलग है। यहां यह भी देखना जरूरी है कि कम्युनिकेशन(संचार) सिर्फ सूचनाओं का हस्तांतरण नहीं है। बल्कि पक्षधरता के साथ, न्याय के लिए खड़ा होना भी है। जन को ताकतवर बनाना भी है। अवसर की समानता की अवधारणा को प्रचारित और स्थापित करना भी है।

विकेन्द्रीकरण ने विकास के सामने कई नए प्रश्न खड़े किए हैं। जिनके भी ठोस और वाजिब हल हमें ढूंढने चाहिए। जैसे पंचायती राज में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। सत्ता इसके चलते पंचायतों तक पहुंची, पर सवाल यह है कि क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है? क्या संसदीय राजनीति और चुनावों की तमाम बुराईयां हमारी पंचायतों तक नहीं पहुंच गयी? वहीं हम मीडिया को देखें तो उसका भी विस्तार हुआ है। व्यापकता बढ़ी है, पहुंच भी बढ़ी है। पर सवाल यह है कि क्या मीडिया में संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता और विविधता को आदर देने की उसकी भावना भी बढ़ी है, तो शायद उत्तर नकारात्मक ही हो। तीनों तंत्रों (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) से निराश लोग मीडिया की ओर बहुत उम्मीदों से देखते हैं। कई अर्थों में सत्ता का तो विकेन्द्रीकरण दिखता है, किंतु मीडिया धीरे-धीरे केन्द्रीकरण का शिकार हो रहा है। इसलिए जरूरी है क्रास मीडिया ओनरशिप के बारे में भी भारत जैसे देश सोचें। ताकि मीडिया के एकाधिकार के खतरों से बचा जा सके। इसके साथ ही प्रेस कौंसिल जैसी नख-दंत हीन संस्था के अधिकारों और क्षेत्राधिकार में बदलाव करते हुए उसे मीडिया कौंसिल में बदला जाना जरूरी है ताकि वह आज के प्रभावी मीडिया को भी अपनी चर्चा में ले सके।

हम जिस संकट से दो चार हैं, वह यह है कि सूचनाएं बढ़ गई हैं और खबरें घट गई हैं। अखबारों के पन्ने बढ़ गए हैं, किंतु इनसे आम-आदमी गायब है। चैनल अब चौबीस घंटे कुछ बोलते हैं, पर उनमें विकास और जनता के सवालों की जगह बहुत कम है। जबकि विकास की पत्रकारिता की मुक्ति इसमें है कि जो लोग मीडिया तक नहीं पहुंच सकते, मीडिया उन तक पहुंचे। उनका दर्द सुने। अच्छी और उम्मीद जगाने वाली खबरों की ओर जाएं।

हमारी राजनीति बदल रही है, हमारा समाज बदल रहा है किंतु हमारे मीडिया के सोचने और अभिव्यक्त करने की शैली उस तुलना में नहीं बदली जैसी बदलनी चाहिए। आज यह मान्यता बन चुकी है कि विकास भारतीय मीडिया की प्राथमिकता नहीं है, शायद समाज भी उसकी प्राथमिकता नहीं है। हमारे नागरबोध ने मीडिया को समाज से बड़ा बना दिया है। किंतु यह तय मानिए कि कोई भी मीडिया, कोई भी राजनीति और कोई भी व्यक्ति समाज से बड़ा नहीं हो सकता। 18 से 25 साल और 18 से 35 साल के युवाओं के बीच बाजार खोज रहे मीडिया की चिंताएं अलग हो सकती हैं किंतु समाज की चिंताएं कुछ भिन्न हैं। वे ही वास्तविक चिंताएं हैं। मीडिया अगर इन चिंताओं से अलग व्यवहार कर रहा है तो वह अपने अस्तित्व पर संकट स्वयं रच है। विश्वसनीयता और प्रामणिकता के संकट तो उसके साथ संयुक्त हैं ही। मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के लिए यह सोचने का सही समय है कि जब सारा देश विकास और सुशासन के सवालों पर गंभीर हो रहा है, उसमें अपने शासकों से जवाब मांगने की हिम्मत आ रही है, तो हमारा मुख्यधारा का मीडिया क्या कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल मीडिया के नेतृत्वकर्ताओं के सामने आज उपस्थिति हैं, अगर इन सवालों के हल हमने आज नहीं तलाशे तो कल बहुत देर हो जाएगी।

मोहल्ले में भी हो गया राजीनामा

कटाक्ष

डॉ. महेन्द्र अग्रवाल
लेखक व्यंग्यकार हैं।

मोहल्ले में पिछले दो महीने से लड़ाई चल रही थी ।रामजीलाल और भैरवनाथ दोनों एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे पर दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था ।यूं पस्त होने के भाव उनके चेहरे से साफ-साफ दिखाई दे रहे थे मगर दोनों में से किसी ने भी अपनी नजरें या चेहरा अभी तक नीचे नहीं किया था। वाक युद्ध में भी दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे ।हाव-भाव और संकेत से भी दोनों की आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई थी ।राम प्रसाद जी की टांग टूट गई थी ,बायी टांग की नीचे की हड्डी टिबियो फिबुला में से फिबुला टूट कर अलग हो गई थी ।एड़ी में भी फ्रैक्चर होने से सूजन आ गई थी। दायां हाथ भी कंधे के बल धरती पर गिर पड़ने के कारण अब ऊपर की ओर उठने से साफ इनकार कर रहा था ।तीन उंगलियां मुड़ गईं तो अब सीधी होने से इंकार कर रही थीं। उधर भैरवनाथ का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था।उनके सीने में राम प्रसाद के सिर के सीधे वार से सीने की बांयी ओर की दो पसलियां टूट गई थीं।दो दांत टूट कर बाहर आ गये थे।मुंह में खून भर गया था और किसी को न दिखाने की इच्छा के बावजूद होठों की कोर से रिसने लगा था।दांयी ओर की एक आंख बंद हो गई थी और सूजन बढ़कर बांयी आंख की किनोर को चूमने लगी थी।यहां तक कि आधी बंद सी प्रतीत हो रही थी ।

दरअसल इस लड़ाई में रामप्रसाद को अपने पड़ोसी विशंभर का रणनीतिक सहयोग मिल रहा था तो भैरवनाथ को किशना और गोपाल का। यह भी एक दूसरे के घोर विरोधी थे और मोहल्ले की पिछली लड़ाईया में अपने अपने विरोधियों से दो-दो हाथ कर चुके थे । तब इन्हें भी अपनी लड़ाई में इसी तरह का गुपचुप सहयोग मिलता रहा था । कभी कोई किसी की वित्तीय मदद कर देता तो कभी कोई किसी को आगे बढ़कर एनर्जी ड्रिंक पिला देता। कभी कोई प्रशासनिक या विधिक सहायता उपलब्ध करा देता। लेकिन इन सहयोगियों के होने से दुश्मनों में से किसी का भी जोश ठंडा नहीं पड़ता था। यूं देखने दिखाने को सबके सामने यह तटस्थ बने रहते और एक दूसरे को लड़ाई बंद कर शांति से बैठकर बात करने का अनुरोध करते । पर मोहल्ले के लोग सब समझते थे और इनके पचड़े में पड़ने से बचते थे।अब भले क्यों लड़ाई झगड़े में फंसे,सो ये भी मनमर्जी करते रहते।

दोनों थक गए थे पर चूंकि नाक का सवाल था तो पहले कौन अपनी नाक पर मक्खी बैठने दे? दूसरे की नाक पर मक्खी बैठ जाए तो वह भी ढीला पड़ जाए। आखिर जो पर्दे के पीछे से खेल कर रहे थे वही काम आए । रात के अंधेरे में उन्होंने ही नकाब ओढ़ कर मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दोनों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान कर घोषणा कर दी कि इस पखवाड़े दोनों बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। इसी बीच दोनों हरदयाल के घर में बैठकर आगे की राजीनामा की शर्तें तय कर लेंगे ताकि पूर्ण शांति हो सके। मोहल्ले में सभी ने इस युद्ध विराम की घोषणा पर दोनों को बधाई देते हुए यही कहा कि मोहल्ले की शांति बहाली की दिशा में यह राहत भरी खबर है ,इससे मोहल्ले के बाकी लोग भी चैन से सो सकेंगे।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. प्रेमचंद द्वितीय
लेखक व्यंग्यकार हैं।

अजब गजब प्रचार से अजब गजब ढहाते उम्मीदवार

हमारी कॉलोनी में दो जुड़वा भाई रहते हैं जब एक जैसे चेहरे, कद, काठी के दोनों हुए तो माता-पिता ने उनमें से एक का नाम अजब और दूसरे का नाम गजब रख दिया । इनका नाम अजब गजब इसलिए रखा कि कलयुग में अजब गजब की यह जोड़ी अजब गजब धूम मचाएगी । इस तरह अजब और गजब तरह-तरह के नुस्खे इजाद करने लगे ।अजब गजब,अजब- गजब,तरीके अपनाने लगे ।कुल मिलाकर अजब गजब अनेक क्षेत्रों में रोल मॉडल बन गए!

अजब गजब का इतना मर्तबा बढ़ गया कि घर में, ऑफिस में,व्यापार में, सामाजिक कार्य में,आध्यात्मिक रूझान में,आर्थिक क्षेत्र में, यहां तक की राजनीति में भी अजब गजब की तरह अजब -गजब तरीके अपनाए जाने लगे ।जब राजनीति में सत्ता में आने के लिए रेवड़ी कल्चर चला तो माले मुफ्त,दिल ए बेरहम और मुफ्त खोरी के कारण जिन्हें सत्ता हासिल नहीं हुई वे लोग धिक्कारने लगे। लेकिन इस कल्चर को छोड़,अजब गजब, कल्चर को कुछ उम्मीदवारों ने अपनाया तो जो उम्मीदवार अपनी,अजब गजब, हरकत नहीं करने से राजनीति से जो बाहर हो रहे थे उनके जीवन में, बहार, आ गई। चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा अजब गजब तरीकों से उम्मीदवार.चुनाव जीतने में लग गए। अभी चल रहे चुनाव में उम्मीदवारों ने,अजब गजब, प्रचार किया। और अजब गजब से अजब गजब ढहाने लगे। उन्होंने जनसंपर्क का अजब गजब तरीका अपनाया,वोटर को लुभाने के लिए कोई उम्मीदवार पकोड़े तल रहा हैं और इस अजब गजब हरकत को अजब गजब तरीके से देख कुछ उम्मीदवार घर में चूल्हे चौके में जाकर रोटियां बेल रहे है वे रोटी बेल कर अलग-अलग तरीके से अपने विरोधी उम्मीदवार के चुनाव के बाद बेल,न होने और जेल में पहुचाने की अजब गजब बातें पेल रहे है। एक ने तो अजब गजब की पराकाष्ठा कर दी,वह सड़क किनारे बैठकर लोगों की हजामत बनाने का अजब गजब खेल करने लगा। चुनाव में उसने दाढ़ी में हाथ डालने से लेकर दाढ़ी बनाने तक का अजब गजब. तरीका अपनाया। एक उम्मीदवार को अजब गजब सोच आया। वह नेत्र विशेषज्ञ होने से आंखों की जांच कर मतदाता की वोट देने की नजर भापने के लिए आंखों का इलाज कर रहा ।यही नहीं कोई उम्मीदवार अजब गजब राजस्थानी,कश्मीरी ढोल से चर्चित हो रहे है। कोई अपने चुनाव चिन्ह को गले में स्टेथ स्कोप की तरह लगाकर बीमार की फीस नहीं लेकर मतदाताओं को फांस रहे हैं। अजब गजब चुनाव प्रचार को देखकर छूट भैया से माननीय बनने की इन जुड़वा अजब गजब भाइयों ने जब चुनाव लड़ने की ठानी तो अजब गजब तौर तरीकों से चुनाव जीत गए ।फिर क्या था अब दोनों एक जैसे सफेद चक,कलफदार कपड़े पहनने लगे, एक जैसी दाढ़ी कटिंग ,एक जैसे शूज, वे जब अजब गजब दिखने से चर्चा में आने लगे तो उन्होंने हर जगह निमंत्रण आने लगे अजब गजब की जोड़ी जब अभी अतिथि के रूप में जाकर अजब गजब हरकत करती तो लोग अजब गजब ठहाके लगाकर उनके अजब गजब जलवे को और प्रभावी बना देते हैं। अजब गजब हमेशा इसलिए खुश रहते हैं की अजब प्रेम की गजब कहानी इन्हीं को लेकर बनी है और गजब है तेरी माया इसे कोई समझ नहीं पाया,जब अजब जुदा तो गजब भी जुदा रहता।

अजब के साथ गजब की हरकतों ने अनेक फैसले और हकीकतों का गजब आईना लोगो को बता दिया। अजब गजब दुनिया में अजब गजब के आइकॉन हो गए।

अजब गजब में से अजब, जब अजब की ड्रेस पहन कर गजब की भीड़ में पहुंचा तो अजब पॉजिटिव लगने लगा और गजब, गजब की भीड़ के कारण नेगेटिव दिखने लगा।इस तरह अजब गजब के खेल ने अजब गजब के दौर में हर कदम अजब तौर पर उठा कर गजब ढहा दिया!

अंधेरे में खोता बचपन

ममता कुशवाहा

लेखक शिक्षक हैं।

तस्करी और अपराध के शिकंजे में नौनिहाल

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में बाल तस्करी का जाल एक संगठित अपराध के रूप में उभर चुका है। यह केवल सीमित क्षेत्रों या राज्यों तक सिमटा हुआ मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। बच्चों की तस्करी के पीछे कई कारण काम करते हैं- गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, और प्रशासनिक ढांचे की कमजोरियां। गरीब और हाशिए पर खड़े परिवारों के बच्चे इस अपराध का सबसे आसान शिकार बनते हैं। जब कोई परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है, तब एक बेहतर भविष्य का झूठा सपना दिखाकर या लालच देकर बच्चों को आसानी से फंसाया जा सकता है। यही कारण है कि बाल तस्करी केवल अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक -आर्थिक असंतुलन का भी दुष्परिणाम है।

किसी भी सभ्य समाज का सबसे कोमल, सबसे संवेदनशील और सबसे संभावनाशील पक्ष उसका बचपन होता है। बच्चे केवल परिवार की आशा नहीं होते, वे राष्ट्र की आत्मा के भविष्य का प्रारूप भी होते हैं। किंतु आज का यथार्थ इस आदर्श से एकदम विपरीत दिखाई देता है। यह विडंबना ही है कि जिन बच्चों को हम 'देश का भविष्य' कहकर गौरवान्वित होते हैं, वही बच्चे आज बहुस्तरीय खतरों, असुरक्षाओं और शोषण के अंधेरे में धकेले जा रहे हैं। बाल तस्करी, बाल श्रम, यौन शोषण, बाल अपराध, भीख मंगवाने वाले गिरोह, और डिजिटल माध्यमों के जरिए बढ़ते नए खतरे, इन सभी ने बचपन को एक असुरक्षित और भयावह अनुभव बना दिया है।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में बाल तस्करी का जाल एक संगठित अपराध के रूप में उभर चुका है। यह केवल सीमित क्षेत्रों या राज्यों तक सिमटा हुआ मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। बच्चों की तस्करी के पीछे कई कारण काम करते हैं- गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, और प्रशासनिक ढांचे की कमजोरियां। गरीब और हाशिए पर खड़े परिवारों के बच्चे इस अपराध का सबसे आसान शिकार बनते हैं। जब कोई परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है, तब एक बेहतर भविष्य का झूठा सपना दिखाकर या लालच देकर बच्चों को आसानी से फंसाया जा सकता है। यही कारण है कि बाल तस्करी केवल अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक असंतुलन का भी दुष्परिणाम है।

कोविड-19 महामारी ने इस संकट को और भी गहरा कर दिया। लॉकडाउन, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था के बाधित होने से लाखों बच्चे स्कूलों से दूर हो गए और असुरक्षा के घेरे में आ गए। अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना मुश्किल हो गया। इस स्थिति का लाभ तस्करों और संगठित गिरोहों ने उठाया। महामारी के बाद लापता बच्चों के मामलों में जो तेजी आई, वह इस बात का प्रमाण है कि संकट के समय बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर पड़ जाती है।

बाल तस्करी के स्वरूप को समझना भी आवश्यक है। यह केवल बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे शोषण की एक लंबी श्रृंखला जुड़ी होती है। तस्करी के शिकार बच्चों को जबरन मजदूरी, घरेलू काम, कारखानों में खतरनाक काम, यौन शोषण, बाल विवाह, अवैध गोद लेने और यहां तक कि अपराध के नेटवर्क में भी धकेला जाता है। यह एक ऐसा अंधकारमय संसार है, जहां से लौट पाना अधिकांश बच्चों के लिए संभव नहीं होता। जो बच्चे बच भी जाते हैं, उनके मानसिक और शारीरिक घाव जीवन भर उनका पीछा करते हैं।

इस समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रशासनिक तंत्र और सरकारें इस मुद्दे को लेकर जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए, उतनी नहीं दिखा पा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कई राज्यों का लापरवाह रवैया यह दर्शाता है कि इस विषय को अभी भी प्राथमिकता के स्तर पर नहीं रखा गया है। आवश्यक रिपोर्टों का समय पर प्रस्तुत न होना, राज्यस्तरीय समितियों का गठन न होना और तस्करी रोधी इकाइयों की कमजोर स्थिति, ये सभी संकेत हैं कि समस्या के समाधान के लिए इच्छाशक्ति की कमी है। यह स्थिति तब और अधिक चिंताजनक हो जाती है जब यह समझ आता है कि इन बच्चों का अधिकांश हिस्सा समाज के सबसे कमजोर वर्गों से आता है, जिनकी आवाज पहले ही बहुत कमजोर होती है।

लापता बच्चों का मुद्दा भी बाल तस्करी से गहराई से जुड़ा हुआ है। हर साल हजारों बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं, और उनमें से कई का कोई पता नहीं चल पाता। जो बच्चे मिल जाते हैं, वे भी अक्सर शोषण का शिकार होकर लौटते हैं। लेकिन जो बच्चे कभी वापस नहीं आते, उनकी कहानी अनकही रह जाती है। यह प्रश्न केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि उन अनगिनत परिवारों की पीड़ा का है, जो अपने बच्चों के लौटने की उम्मीद में हर दिन जीते हैं। एक मां-बाप के लिए अपने बच्चे का यूं खो जाना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक नैतिक असफलता है।

इसमें सुधार के लिए न्यायपालिका ने कई महत्वपूर्ण कदम सुझाए हैं, जैसे कि तस्करी के मामलों में त्वरित सुनवाई, जांच प्रक्रिया में सुधार, और तस्करी रोधी इकाइयों को सशक्त बनाना। लेकिन केवल निर्देश देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन न हो। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही, और समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। समाज की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाल तस्करी केवल सरकारी विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनहीनता का भी परिणाम है। जब हम अपने आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को नजरअंदाज करते हैं, जब हम किसी बच्चे को शोषण की स्थिति में देखकर भी चुप रहते हैं, तब हम अनजाने में इस अपराध को बढ़ावा देते हैं। हमें यह समझना होगा कि बच्चों की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। जागरूकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के बिना इस समस्या से लड़ना संभव नहीं है।

शिक्षा इस समस्या के समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम हो सकती है। यदि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित वातावरण मिले, तो वे तस्करी और शोषण के जाल में फंसने से बच सकते हैं। साथ ही, अभिभावकों को भी जागरूक करना जरूरी है, ताकि वे अपने बच्चों को इस प्रकार के खतरों से बचा सकें। डिजिटल युग में साइबर अपराध और ऑनलाइन तस्करी के नए खतरे भी सामने आ रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए विशेष रणनीतियों की आवश्यकता है। सचमें यह समस्या केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे समय की नैतिक परीक्षा है। यह तय करेगा कि हम एक समाज के रूप में कितने संवेदनशील, जिम्मेदार और मानवीय हैं। यदि हम अपने बच्चों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन नहीं दे सकते, तो हमारे विकास और प्रगति के सभी दावे खोखले साबित होंगे। यह आवश्यक है कि हम इस समस्या को केवल आंकड़ों और नीतियों के दायरे में न देखें, बल्कि इसे एक मानवीय संकट के रूप में समझें और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करें।

बचपन को बचाना दरअसल भविष्य को बचाना है। यदि आज हम अपने बच्चों को इस अंधेरे से नहीं निकाल पाए, तो आने वाला कल केवल और अधिक भयावह होगा। इसलिए यह समय है कि हम संवेदनहीनता की चादर को हटाकर अपने भीतर की मानवता को जगाएं और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में असुरक्षित और असहाय महसूस न करे। तभी हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहां बचपन सच में सुरक्षित, स्वतंत्र और खुशहाल हो।

किसानों के लिए समाधान या नया जाल?

कार्बन मार्केट्स

निलेश देसाई

लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं।

कार्बन मार्केट्स का विचार मूलत: विकसित देशों और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपज है। ये कंपनियाँ अपने भारी उत्सर्जन को कम करने के बजाय उसे 'ऑफसेट' करने का रास्ता खोजती हैं। इसके लिए वे भारत जैसे विकासशील देशों के किसानों की जमीन को कार्बन सोखने वाले 'स्पंज' की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। असली प्रदूषक औद्योगिक देशों में बैठे हैं, लेकिन जलवायु सुधार की जिम्मेदारी और निगरानी का बोझ भारत के छोटे किसानों के कंधों पर डाला जा रहा है। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे कदम उठाए हैं। कृषि मंत्रालय ने भी 'स्वैच्छिक कार्बन मार्केट' का ढांचा पेश किया है। कागजों पर यह आधुनिक दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन नीतियों में छोटे किसानों की सुरक्षा और उनके लाभ का हिस्सा बेहद धुंधला है। 10 से 20 साल के कठोर अनुबंध किसान की जमीन को कॉर्पोरेट निगरानी के हवाले कर देते हैं।

गाँव की सरहद पर अपनी मेड़ पर खड़ा किसान जब आसमान की ओर देखता है, तो उसकी आँखों में बारिश की उम्मीद से कहीं ज्यादा अनिश्चितता का डर होता है। जलवायु परिवर्तन ने खेती को पसीने से ज्यादा 'किस्मत' का जुआ बना दिया है। इसी संकट के बीच, वैश्विक कॉर्पोरेट जगत एक नया सपना लेकर आया है- 'कार्बन की खेती'। दावा किया जा रहा है कि अब किसान हवा से कार्बन सोखकर मुनाफा कमाएंगे। लेकिन क्या यह वास्तव में अन्नदाता का उद्धार है, या यह एक नई तरह की 'हरित गुलामी' की शुरुआत है?

कार्बन मार्केट्स का विचार मूलतः विकसित देशों और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपज है। ये कंपनियाँ अपने भारी उत्सर्जन को कम करने के बजाय उसे 'ऑफसेट' करने का रास्ता खोजती हैं। इसके लिए वे भारत जैसे विकासशील देशों के किसानों की जमीन को कार्बन सोखने वाले 'स्पंज' की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। असली प्रदूषक औद्योगिक देशों में बैठे हैं, लेकिन जलवायु सुधार की जिम्मेदारी और निगरानी का बोझ भारत के छोटे किसानों के कंधों पर डाला जा रहा है।

भारत सरकार ने हाल के वर्षों में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे कदम उठाए हैं। कृषि मंत्रालय ने भी 'स्वैच्छिक कार्बन मार्केट' का ढांचा पेश किया है। कागजों पर यह आधुनिक दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन नीतियों में छोटे किसानों की सुरक्षा और उनके लाभ का हिस्सा बेहद धुंधला है। 10 से 20 साल के कठोर अनुबंध किसान की जमीन को कॉर्पोरेट निगरानी के हवाले कर देते हैं।

कार्बन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह जलवायु परिवर्तन के 'जोखिम' को उसी पर डाल देता है जो इसका सबसे बड़ा शिकार है। यदि सूखा, बाढ़ या कीटों के हमले से खेत की कार्बन सोखने की क्षमता घटती है, तो सजा किसान को मिलती है। उसका भुगतान रोक दिया जाता है या उस पर जुर्माना लगाया जाता है। कंपनियाँ और बिचौलिये सुरक्षित रहते हैं, जबकि किसान इस चक्रव्यूह की सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है।

जब 'कार्बन डॉलर' का बंटवारा होता है, तो अंतरराष्ट्रीय दलाल, डेटा एजेंसियां और तकनीकी सलाहकार उसका बड़ा हिस्सा डकार जाते हैं। किसान तक पहुँचने वाली राशि इतनी कम होती है कि वह एक बोरी खाद की कीमत भी पूरी नहीं कर पाती। साथ ही, यह मॉडल भारतीय कृषि की रीढ़–महिला किसानों–को पूरी तरह अदृश्य कर देता है। भुगतान केवल जमीन के मालिक को मिलता है, जबकि मिट्टी को सहेजने वाली महिलाओं और भूमिहीन श्रमिकों का इसमें कोई स्थान नहीं है।

यदि किसान केवल कार्बन क्रेडिट के लालच या दबाव में आकर फसल पैटर्न बदलने लगें, तो देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? अनाज और दालों की जगह 'कार्बन-फ्रेंडली' फसलों को प्राथमिकता देना 'हवा साफ करने' के नाम पर 'थाली खाली' करने जैसा हो सकता है। सबसे बड़ा हमला किसान की स्वतंत्रता पर है। अनुबंध के बाद किसान यह तय नहीं कर सकता कि उसे अपनी जमीन पर क्या और कैसे बोना है। वह अन्नदाता से एक 'अनुबंध-मजदूर' में बदल जाता है।

किसानों को बाजार के रहमों-करम पर छोड़ना आत्मघाती होगा। हमें पीईएस (पेमेंट इकोसिस्टम सर्विसेस) जैसे मॉडल की जरूरत है, जहाँ किसान को केवल कार्बन के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी सुधार, जल संरक्षण और जैव विविधता के लिए सीधे सार्वजनिक वित्त से समर्थन मिले। यह 'प्रदूषक भुगतान करे' (पाल्यूटर पेज़ प्रिंसिपल) के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन से लड़ाई जरूरी है, लेकिन यह किसान की गरिमा और स्वायत्तता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। भारत को ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो किसानों को 'कॉर्पोरेट नेट-जीरो' का साधन बनाने के बजाय उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र के रक्षक के रूप में सशक्त करें।

विश्व-रंग

डॉ. सुधीर सक्सेना

मेलोनी और ट्रंप के रिश्तों में खटास

ट्रंप के वक्तव्य और मेलोनी के प्रति-वक्तव्य से स्पष्ट है कि अमेरिका और इटली के मध्य दरार दिनों-दिन चौड़ी होती जा रही है। विश्व की सर्वोच्च ताकत अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते ट्रंप तमाम देशों को तुच्छ या दबैल मानने की 'ग्रंथि' से पीड़ित हैं और जब-तब उन्हें धमकाते या गरियाते रहते हैं। वह किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिष्ठित व्यक्ति का मखौल उड़ाने अथवा तंज कसने में भी बाज नहीं आते। गत दिनों कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु पोप ने उन्हें आईना दिखाया, किंतु उसके बाद भी वह अपने बड़बोलेपन पर अड़िग रहे। उनके बयान की इतालवी संसद में तीखी प्रतिक्रिया हुई और इटली के सर्वोच्च सदन में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने एक सुर में ट्रंप के बयान पर ऐतराज जताया। इतालवी संसद में नेता प्रतिपक्ष सुश्री एली श्लेन ने गरजते हुये कहा कि कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मेरे देश और मेरी सरकार का अपमान नहीं कर सकता। ट्रंप को खरी खोटी सुनाते हुये श्लेन ने दो टूक कहा – 'सुन लो, ट्रंप। भले ही हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हों, लेकिन हम इतालवी जने अपने देश पर होने वाले हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर तुम्हारी तरफ है।'

इतिहास गवाह है कि दुनिया के नौ देशों पास परमाणु बम हैं, लेकिन केवल एक ने ही अब तक उनका इस्तेमाल किया है और वो देश..... अमेरिका है। यह कहना है जियोर्जिया मेलोनी का। जियोर्जिया मेलोनी योरोपीय राष्ट्र इटली की प्रधानमंत्री है, निर्वाचित प्रधानमंत्री। यह बात उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस आशय के बयान के उत्तर में कही, जिसमें ट्रंप ने ईरान के 'इस्लामी बम' से लोगों को डराया था और गैर-इस्लामी मुल्कों का समर्थन हासिल करना चाहा था। ट्रंप योटोपीय देशों को 'हौव्वा' दिखाकर आगाह करना चाहते थे कि सावधान, अगर ईरान के हाथों में बम आ गया, तो तुम्हारा क्या हश्र होगा?

ट्रंप के वक्तव्य और मेलोनी के प्रति-वक्तव्य से स्पष्ट है कि अमेरिका और इटली के मध्य दरार दिनों-दिन चौड़ी होती जा रही है। विश्व की सर्वोच्च ताकत अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते ट्रंप तमाम देशों को तुच्छ या दबैल मानने की 'ग्रंथि' से पीड़ित हैं और जब-तब उन्हें धमकाते या गरियाते रहते हैं। वह किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिष्ठित व्यक्ति का मखौल उड़ाने अथवा तंज कसने में भी बाज नहीं आते। गत दिनों कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु पोप ने उन्हें आईना दिखाया, किंतु उसके बाद भी वह अपने बड़बोलेपन पर अड़िग रहे। उनके बयान की इतालवी संसद में तीखी प्रतिक्रिया हुई और इटली के सर्वोच्च सदन में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने एक सुर में ट्रंप के बयान पर ऐतराज जताया। इतालवी संसद में नेता प्रतिपक्ष सुश्री एली श्लेन ने गरजते हुये कहा कि कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मेरे देश और मेरी सरकार का अपमान नहीं कर सकता। ट्रंप को खरी खोटी सुनाते हुये श्लेन ने दो टूक कहा - 'सुन लो, ट्रंप। भले ही हम राजनीतिक कि प्रतिद्वंद्वी हों, लेकिन हम इतालवी जने अपने देश पर होने वाले हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर तुम्हारी तरफ है।'

इटली की सेंट्रल लेफ्ट विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक- पार्टी की नेत्री श्लेन की मेलोनी के साथ एकजुटता ने ट्रंप को बेतरह हैरान कर दिया है। कुछ अर्सा पहले तक मेलोनी ट्रंप की विश्वसनीय सखी समझी जाती थीं। एक छमाही पहले की बात है, जब शर्म-अल-शेख में मेलोनी और तमाम नेता गाजा शांति योजना पर विचार के लिये एकत्र हुये थे। तब ट्रंप ने मेलोनी की शान में कसीदे काढ़ते हुये कहा था- 'यू डोंट माइंड बीइंग काल्ड ब्यूटीफुल, राइट' मेलोनी की ओर मुखातिब ट्रंप के बोल थे - आप वाकई खूबसूरत हैं, आपके आने का शुक्रिया। ट्रंप की तारीफ से मेलोनी असहज तो हुईं, लेकिन उन्होंने तारीफ कुबूल कर स्वयं को ट्रंप की सच्ची दोस्त साबित करने में कसर नहीं उठा रखी थी। यही नहीं, वह ट्रंप के पदग्रहण पर भी गयीं और फ्लोरिडा में उनके मार-अ-लागो कंट्री क्लब का फौरी दौरा भी किया। मगर उनका यह रिश्ता कपूर की नाईं उड़ गया। इसी हफ्ते एक इतालवी पत्र को दिये इन्टरव्यू में ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देने के लिये मेलोनी को आड़े हाथों लेते हुये कहा कि उनमें साहस की कमी है। ट्रंप ने मेलोनी के रवैये को नाकाबिले-बर्दाश्त बताते हुये कहा कि मेलोनी को इस बात की फिक्र नहीं है कि यदि इटली के पास परमाणु बम होता तो वह दो मिनट में उड़ा देता। ट्रंप ने मेलोनी पर यह फबती तब कसी, जब मेलोनी इटली में घरेलू मोर्चे पर अपनी छवि और नीतियों को लेकर विवादों में उलझी हुई थीं। ट्रंप के प्रति झुकाव के लिये भी वह नुक्ताचीं की शिकार थी और शर्म-अल-शेख में ट्रंप के 'कमेंट' की भी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। अपनी छवि सुधारने के लिये मेलोनी को मौके की तलाश थी और पोप-प्रकरण ने उन्हें वह मौका थमा दिया। मेलोनी यह बखूबी जानती हैं कि इटली में लाग पोप से प्यार और युद्ध से घृणा करते हैं। इतालवी जनों की इस मनोदशा का मेलोनी ने लाभ उठाया और 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका-इस्रायल के साझा हमले के बाद ट्रंप से फासला बरतने का क्रम शुरू हुआ। उन्होने सतर्कतापूर्वक ईरान और अमेरिका से 'सम-दूरी' की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि हमें अयातुल्लाहो का ऐसा ईरान नहीं चाहिये, जिसके पास अणु बम है और जो इटली और योरोप का डराये। ऐसे ही उन्होंने ईरान-अमेरिका जंग में अमेरिका की मदद के लिये इतालवी फौजी भेजने से इंकार कर दिया।

इसमें शक नहीं कि मेलोनी अपनी छवि को लेकर अत्यंत सचेत हैं। रेफेरेंडम में पराजय ने अतिरिक्त सचेत बना दिया है। इसी के चलते उन्होंने अमेरिका को ताजा जंग में सिसिली के एयरबेस में उपयोग की इजाजत नहीं दी। अमेरिका चाहता था कि उसके फ़ौजी विमानों को यह सुविधा मिले। उनकी सतर्कता का आलम यह था कि वह पोप प्रकरण पर कुछ नहीं कहना चाहती थीं, लेकिन विपक्ष ने उन्हें स्पष्ट रुख अख्तियार करने को बाध्य कर दिया। उन्होंने कहा कि शांति की बहाली की मांग पोप का हक है। यकीनन मेलोनी तनी हुई रस्सी पर चल रही हैं, जहां जरा सी चूक घातक हो सकती है। वह जानती है कि इटली में अगले वर्ष आम चुनाव है और इतालवी जनता की वैश्विक घटनाक्रम में अधिक रुचि भले

ही नहीं हो, किंतु ईरान-अमेरिका की जंग लंबी खिंचने से इतालवियों को मंहगाई और ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। इसी अवधारणा के तहत उन्होंने इस्रायल के साथ सामरिक - संधि तोड़ ली है। फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के कोर स्टार्मर के साथ उनकी मुलाकात पर अमेरिका और सारे योरोप की उत्सुक निगाहें हैं। अंदाजा यही है कि मेलोनी और ट्रंप के रिश्तों में उपजी खटास नये गुल खिला सकती है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत धार जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन; महिलाओं की भागीदारी अब 14% से बढ़कर हुई 33%

धार। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के निर्णयानुसार, इस ऐतिहासिक उपलब्धि को पूरे प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 'नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा' आयोजित किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी सुभाष जैन के निर्देशानुसार, यह उत्सव जिला, विकासखंड, शहरी एवं ग्रामीण परियोजना स्तर पर उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान नारी शक्ति पदयात्रा, दीवार लेखन, संगोष्ठी और व्याख्यान माला जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं, जिनमें महिला समूह, लखपति दीदी और लाडली बहनों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई है।

वन स्टॉप सेंटर, धार द्वारा शहर के चिटनिस चौक क्षेत्र में

आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को बताया गया कि अब वे संसद और विधानसभाओं में 33त्न आरक्षण की पात्र हैं, जिससे वे अपने मत का प्रयोग स्वयं के नेतृत्व के लिए कर सकेंगी। इस अवसर पर पूर्व पार्षद अनीता महालय ने महिलाओं को अधिनियम की बधाई दी। वहीं, आर्य समाज के प्रधान श्री लाखन सिंह ठाकुर ने महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रोत्साहित किया।

सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत जिला भोज चिकित्सालय में भी महिलाओं को अधिनियम की जानकारी दी गई। उन्हें समझाया गया कि समाज में अब उनके अधिकार पुरुषों के समान सुनिश्चित किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को नारी शक्ति वंदन के समर्थन हेतु टोल-फ्री नंबर पर मिस कॉल भी करवाया गया। इस अवसर पर जूडो-कराटे प्रशिक्षक कुमकुम श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

टीकाकरण के महत्व को आमजन को समझना होगा

बैतूल। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला, स्वास्थ्य विभाग जिला, नगर पालिका परिषद द्वारा संयुक्त रूप से नगर पालिका बाल मंदिर सभा कक्ष में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम अंतर्गत स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार महिलाओं के महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष महेश राठौर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर अंतर्गत स्वयं स्वास्थ्य जांच कराई जाकर कार्यक्रम में सम्मिलित आमजनों को शिविर में भाग लेकर इसे सफल बनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। शिविर में स्वास्थ्य जांच कर आवश्यकतानुरूप काउंसलिंग की गई। श्री राय द्वारा शासन की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आमजनों के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण सुविधाएं जैसे समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क वकील, विधिक परामर्श, और लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का त्वरित निपटान की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। साथ ही घरेलू हिंसा से संबंधित कानून, दहेज अधिनियम 1961 और पीड़ित प्रतिकर योजना की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा अधिकारी रत्नेश खाड़े एवं एपीएम प्रकाश मकोड़े द्वारा एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत एचपीवी वैक्सीन की निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर निशुल्क उपलब्धता की जानकारी दी साथ ही एचपीवी वैक्सीन के विषय में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने वाली इस वैक्सीन के बारे में फैली भ्रांति को दूर दिया।

स्लॉट बुक नहीं होने से किसान हो रहे परेशान, खरीदी की रफ्तार भी पड़ी धीमी

सैटेलाइट इमेजिंग और पटवारी के गिरदावरी डेटा के बीच अंतर

एस. द्विवेदी, बैतूल। जिले में गेहूं की सरकारी खरीदी जारी है, लेकिन किसानों को अपनी ही फसल बेचने के लिए सोसायटी और तहसील के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण सैटेलाइट इमेजिंग और पटवारी के गिरदावरी डेटा के बीच का अंतर है। शासन ने इस बार पारदर्शिता के लिए सैटेलाइट डेटा अनिवार्य कर दिया है, लेकिन फील्ड स्तर पर विसंगतियों के कारण सत्यापन की प्रक्रिया किसानों के लिए गले की फांस बन गई है। वर्तमान में जब किसान स्लॉट बुक कर रहा है, तब उसे पता चल रहा है कि उसका डाटा मिसमैच है। दरअसल सेटेलाइट के माध्यम से हुई गिरदावरी में कई बार फसल की पहचान गलत हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसान ने खेत के एक हिस्से में सरसों और बड़े हिस्से में गेहूं बोया है, तो तकनीक कभी-कभी पूरे रकबे को अन्य फसल में दिखा देती है। इससे गेहूं बेचने के लिए पंजीकृत रकबा कम या शून्य हो जाता है। इस खामी को देखते हुए शासन ने निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों के डेटा में विसंगति है, उनका भौतिक सत्यापन पटवारी करेंगे। अब समस्या यह आ रही है कि पटवारियों ने जो डेटा सारा ऐप पर फोटो खींचकर अपलोड किया है, उसी को दोबारा प्रतिवेदन के साथ सत्यापित करना पड़ रहा है। इस दोहरी प्रक्रिया और सर्वर डाउन होने से समय लग रहा है।

लिखित प्रतिवेदन की अनिवार्यता से भी बढ़ी परेशानी- बताया जा रहा है कि पटवारियों को अब लिखित में प्रतिवेदन भी देना पड़ रहा है। जब तक यह

प्रतिवेदन सोसायटी और पोर्टल पर अपडेट नहीं होता, तब तक किसान का स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि तकनीकी खामी, सत्यापन प्रक्रिया खरीदी शुरू होने से पहले ही पूरी कर ली जानी चाहिए थी। अब किसानों को डर है कि स्लॉट बुक न होने से सरकारी खरीदी की तारीख न निकल जाए। इस चक्कर से बचने के लिए कई किसान मजबूरी में अपनी उपज व्यापारियों को औने-पौने दामों पर बेच रहे है।

सिर्फ छोटे किसानों के ही हो रहे स्लॉट बुक- पहले गेहूं खरीदी में देरी से किसान परेशान थे। अब स्लॉट बुक नहीं होने से किसानों को चिंता सताने लगी है। मंडी में गेहूं के दाम नहीं मिलने से किसान सरकारी खरीदी में गेहूं बेचने का इंतजार कर रहे हैं। वहां भी 5 एकड़ से कम रकबे के स्लॉट बुक हो रहे हैं। वहीं सैटेलाइट वेरिफिकेशन में किसानों के पंजीयन भी रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके चलते स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रहे है। बता दे कि इस बार गेहूं खरीदी के लिए 18969 किसानों ने पंजीयन करवाए हैं।

सेन्ट पैट्रिक स्कूल में जनगणना 2027 का तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित, एसडीएम भल्लावी ने कहा गुणवत्ता से हो जनगणना

सोहागपुर। सेन्ट पैट्रिक स्कूल में जनगणना 2027 का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका चोपड़ा एवं तहसीलदार आर एस झरबड़े के आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर एसडीएम भल्लावी ने प्रशिक्षणार्थियों को कहा कि उक्त जनगणना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2011 के बाद आयोजित की जा रही है। इस कारण जनगणना के कार्य को उत्कृष्टता पूर्वक करें। ताकि इस जनगणना से कोई व्यक्ति या परिवार ने छूट सके। इस अवसर पर 6मास्टर ट्रेनर बृजेन्द्र वर्मा, विपिन गिल्ला, राकेश रघुवंशी, रामकिशोर दुबे, राहुल तिवारी एवं जितेंद्र तिवारी ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों सुपरवाइजर को प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण प्रदान कर्ताओं ने प्रथम दिवस प्रथम सत्र में कुल 150 प्रशिक्षणार्थियों को 3 कक्षों में व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसमें द्वारा प्रत्येक कक्ष में 2-2 ट्रेनर्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के अवसर पर समस्त प्रशिक्षणार्थियों को जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कार्यप्रणाली विस्तार से समझाई गई। इस जनगणना में अमित मिश्रा, राहुल साहू, संदीप कुशवाहा की उल्लेखनीय भागीदारी रही।

उल्लेखनीय स्वगणनाउल्लेखनीय है कि भारत की जनगणना 2027 में आखिर खास यह है कि पहली बार डिजिटल मोड में आयोजितपहले

चरण में नागरिकों के लिए स्व-गणना (सेल्फ-इन्यूमरेशन) की सुविधाघर बैठे अपनी सारी जानकारी सेल्फ-एन्युमेरेशन पोर्टल के माध्यम से 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 के बीच भरने की सुविधाआवास की स्थिति, परिवार का विवरण, बुनियादी सुविधाओं और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता पर केंद्रित कुल 33 सवाल है। उक्त पोर्टल 17 अप्रैल 2026 से कार्य करेगा। जिसमें सभी प्रश्नों का सत्य/सही उत्तर देना धारा 8 के अंतर्गत अनिवार्य है। अंतिम सबमिशन से पहले, स्व-गणना के माध्यम से दर्ज ऑकड़ों की पर्यवक्षेकों द्वारा की जाएगी स्व-गणना (सेल्फ-इन्यूमरेशन)सरल, सुरक्षित और डिजिटल सुविधा कैसे करें स्व-गणना आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ6 सबमिशन के बाद से आईडी मिलेगा। जिसमें अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी द्वारा लॉगिन करें ।77 से आईडी सुरक्षित रखें। अपना राज्य, जिला और स्थानीय विवरण चुनें। प्रगणक (इन्यूमरेटर) आने पर से आईडी दें।डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करें। प्रगणक जानकारी की पुष्टि करेंगे। विकास, प्रगति, मकान एवं परिवार से संबंधित जानकारी भरें। इसके लाभ समय की बचत सटीक जानकारी दें। याद रखें स्व-गणना एक विशेष सुविधा है। यदि आप स्व-गणना नहीं कर पाते हैं, तो चिंता न करें, निर्धारित अवधि में प्रगणक आपके घर आकर जानकारी अवश्य दर्ज करेंगे।तेज़ डेटा प्रसंस्करण। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेगी। प्रशासन ने आव्हान किया है कि जनता-जनार्दन जनगणना में हिस्सा लें।

पावर प्लांट से पाँच हजार लोगों को मिलेगा रोजगार : उप मुख्यमंत्री

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नवीन सर्किट हाउस सभागार रीवा में आयोजित बैठक में कहा कि टाटा एनर्जी रीवा जिले में ऊर्जा की बड़ी परियोजना शुरू करने जा रही है। टाटा एनर्जी 28 हजार करोड़ रुपए निवेश करके पावर प्लांट स्थापित करने जा रही है। इस प्लांट से एक हजार मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। इससे क्लीन और ग्रीन एनर्जी के साथ-साथ पाँच हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। परियोजना के लिए आवश्यक जमीनें चिन्हित कर ली गई हैं। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम 169 हेक्टेयर जमीन टाटा एनर्जी को आवंटित कर रहा है। शेष जमीनों का अधिग्रहण करके टाटा एनर्जी को उपलब्ध कराएं, जिससे परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। सोलर एनर्जी के बाद यह रीवा जिले के लिए दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा में अधोसंरचना का विकास तेजी से हुआ है। इसका लाभ अब जिले को मिलने लगा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन योदव की विशेष पहल पर रीवा में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कई क्षेत्रों के उद्योगपति रीवा में निवेश के इच्छुक हैं। एयरपोर्ट, सड़क, रेलवे लाइन और पानी की उपलब्धता से निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है। टाटा एनर्जी की परियोजना से जिले के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग तथा वन विभाग के अधिकारी समन्वय से प्रयास करें। बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने बताया कि परियोजना के लिए आवश्यक जमीनें तय समय सीमा में टाटा एनर्जी को उपलब्ध करा

उप मुख्यमंत्री ने झलबदरी तालाब सौन्दर्यीकरण कार्य का किया निरीक्षण

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में झलबदरी तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य एवं मार्तंड क्रमांक 2 के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।

दी जाएंगी। निजी जमीनों को टाटा एनर्जी स्वयं प्राप्त करेगी। प्रशासनिक स्तर पर पूरा सहयोग किया जा रहा है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट से केवल 30 मिनट की दूरी पर मैहर जिले में अमझर में 170 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। एमपीआईडीसी के अधिकारी इसमें निवेश के लिए केन्द्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य योजना) के तहत प्रस्ताव बनाएं। बैठक में एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक यूके तिवारी ने बताया कि अमझर में औद्योगिक पार्क में 50 से अधिक औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित की जाएंगी। औद्योगिक केन्द्र के लिए अतिरिक्त भूमि की भी तलाश की जा रही है। बैठक में सीसीएफ राजेश राय ने कहा कि वन भूमि में अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर समय सीमा में अनुमति जारी कर दी जाएगी। बैठक में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि जिले में निवेश करने वाले उद्यमियों को हर संभव सहायता दी जाएगी। जिले के औद्योगिक विकास में तेजी के लिए निवेश आवश्यक है। अमझर में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क का लाभ भी रीवा जिले को मिलेगा। बैठक में टाटा एनर्जी के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित परियोजना की विस्तार से जानकारी दी। टाटा एनर्जी के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे सहयोग की प्रशंसा की। बैठक में अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, एसडीएम सिरमौर दृष्टि जायसवाल, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी नितिन पटेल तथा टाटा एनर्जी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कटनी में ब्लॉक, 18 अप्रैल को बीना-कटनी मेमू आंशिक निरस्त

मुख्य स्टेशन की जगह कटनी मुडवारा तक ही चलेगी ट्रेन

भोपाल (नप्र)। कटनी रेलवे स्टेशन पर लाइन कार्य के चलते 18 अप्रैल को ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण भोपाल मंडल में संचालित बीना-कटनी मेमू का परिचालन एक दिन के लिए प्रभावित रहेगा।

रेलवे प्रशासन के अनुसार गाड़ी संख्या 11601/11602 बीना-कटनी-बीना मेमू दोनों दिशाओं में कटनी स्टेशन तक नहीं जाएगी। यह ट्रेन केवल कटनी मुडवारा तक ही संचालित होगी। इस वजह से कटनी मुडवारा से कटनी के बीच का हिस्सा 18 अप्रैल को आंशिक रूप से निरस्त रहेगा।

यात्रियों को सलाह

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। इसके लिए अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा एनटीईएस/139 और रेल मदद का उपयोग किया जा सकता है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से किया संवाद

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया।

मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजनों से संवाद कर उनकी जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया। जिन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया जा सका, उन्हें संबंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा गया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उनकी कठिनाइयों को समझा और उन्हें जल्द से जल्द समाधान दिलाने का आश्वासन दिया।

ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम चौक पर चलाया स्वच्छता अभियान

बैतूल। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को सुबह 8 बजे शहर के परशुराम चौक पर स्वच्छता सेवा कार्य का आयोजन विप्र समाज के बैनर तले किया गया। इस अभियान में ब्राह्मण समाज के अलावा सभी वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान परशुराम चौक एवं उसके आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई कर कचरे का उचित निस्तारण किया गया तथा आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी जागृत करती है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान नगर पालिका के पार्षद आनंद प्रजापति, समाजसेवी सुनील द्विवेदी, संजय पप्पी शुक्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास मिश्रा एवं विक्रम शर्मा, मनीष मिसर, पर्यावरणविद तरुण वैद्य, पं. दुबेजी, नीलम दुबे सहित नपा बैतूल की स्वच्छता टीम के स्वच्छता निरीक्षक संतोष धनेलिया एवं बड़ी संख्या में परशुराम सेना के कार्यकर्ता व विप्र समाज के लोग तथा आमजन उपस्थित थे।

स्वच्छता सेवा अभियान - आज परशुराम चौक, बैतूल में स्वच्छता सेवा कार्य का आयोजन किया गया। इस अभियान में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अपना योगदान दिया।

कार्यक्रम के दौरान चौक एवं आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई की गई, कचरे का उचित निस्तारण किया गया तथा आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।

भोपाल में लगे इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद के नारे, दाढ़ी-टोपी वाला पुतला लेकर पहुंचे कार्यकर्ता

नासिक आईटी कंपनी विवाद पर बजरंग दल का प्रदर्शन

भोपाल (नप्र)। महाराष्ट्र के नासिक की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की इकाई में महिला कर्मचारियों के यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव के मामले को लेकर भोपाल में बजरंग दल विरोध कर रहा है। बुधवार को एमपी नगर क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नारे लगाए। इनमें 'इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद', 'देश के गद्दारों को गोली मारो', 'लव जिहाद बंद करो' जैसे नारे शामिल रहे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता दाढ़ी-टोपी वाला पुतला भी लेकर पहुंचे, जिसके साथ उन्होंने प्रदर्शन किया। मौके पर भारी

पुलिस बल तैनात रहा।

पदाधिकारी बोले- यह कॉर्पोरेट जिहाद- बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि नासिक ञ्जष्टस् मामले में सामने आए आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्होंने इसे 'कॉर्पोरेट जिहाद' करार देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन ने पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और ऐसे मामलों पर रोक लगाने की अपील की है।

महिला-पुरुष दोनों ने दर्ज कराई शिकायत- गौरतलब है कि नासिक टीसीएस कार्यालय में 8-9 महिला कर्मचारियों और एक पुरुष ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने टीम लीडर्स और एचआर मैनेजर पर यौन शोषण, धार्मिक दबाव, जबरन धर्म परिवर्तन और संबंध बनाने के लालच में शोषण के आरोप लगाए हैं।

सात आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी गठित- मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।

जनगणना 2027 : प्रगणक पर्यवेक्षकों को मैदानी कार्य से पहले दिया गहन प्रशिक्षण

बैतूल। जिले में जनगणना 2027 को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री डॉ. सौरभ संजय सोनवणे तथा अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती वंदना जाट के निर्देशानुसार प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण 15 से 17 अप्रैल तक जिले में ग्रामीण चार्ज अंतर्गत तहसील आमला, आठनेर, बैतूल, भैंसदेही, भीमपुर, घोड़ाडोंगरी, मुलताई, प्रभातपट्टन तथा शाहपुर में आयोजित कर जनगणना कार्य से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत फील्ड ट्रेनर्स द्वारा 733 प्रगणकों एवं 124 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में प्रतिभागियों को जनगणना का परिचय, कानूनी प्रावधान, प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की भूमिका एवं कर्तव्यों सहित आवश्यक अवधारणाओं एवं परिभाषाओं की जानकारी दी गई। साथ ही एचएलओ मोबाइल एप के प्रभावी उपयोग (यूटिलिटी) एवं उसकी विशेषताओं से अवगत कराया गया। द्वितीय दिवस में एचएलओ एप के 33 प्रश्नों के संकलन की शैली, अवधारणाओं एवं परिभाषाओं पर गहन प्रशिक्षण दिया गया तथा एप के माध्यम से डेटा संकलन एवं सत्यापन की प्रक्रिया बताई गई। तृतीय दिवस में ÷क्या करें एवं क्या न करें÷ तथा डेटा सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही प्रगणकों, पर्यवेक्षकों को फील्ड अभ्यास में परिवारों से संपर्क स्थापित करने की विधि, डेटा प्रविष्टि, त्रुटियों की पहचान, स्वगणना प्रक्रिया, नागरिकों से संपर्क की विधि, संवेदनशील परिस्थितियों में कार्य करने के तरीके एवं शिष्टाचार संबंधी शिष्टाचार प्रोटोकॉल एवं प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को व्यवहारिक अभ्यास के माध्यम से समझाया गया।

संक्षिप्त समाचार

एसडीएम सुश्री बघेल ने उपार्जन केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

हरदा,(निप्र)। समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से बुधवार को खिरकिया एसडीएम सुश्री शिवांगी बघेल ने क्षेत्र के विभिन्न उपार्जन केंद्रों का औचक भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान एसडीएम ने उपार्जन केंद्रों पर अनाज की तुलाई, गुणवत्ता परीक्षण और भंडारण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

21 स्व-सहायता समूहों को उपार्जन कार्य की जिम्मेदारी, महिला सशक्तिकरण के साथ पारदर्शी व्यवस्था की ओर कदम

विदिशा,(निप्र)। विदिशा जिले में समर्थन मूल्य पर फसलों के उपार्जन कार्य को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं सहभागी बनाने के उद्देश्य से इस वर्ष 21 स्व-सहायता समूहों को उपार्जन केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पहल न केवल उपार्जन प्रक्रिया को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों पर चयनित स्व-सहायता समूहों द्वारा पंजीयन सत्यापन, तौल व्यवस्था, रिकॉर्ड संधारण एवं किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन जैसे कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया जा रहा है। इन समूहों को प्रशासन द्वारा पूर्व में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे वे उपार्जन प्रक्रिया की बारीकियों को समझते हुए जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकेंगे। उपार्जन कार्य में स्व-सहायता समूहों की सहभागिता से जहां एक ओर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी अधिक सुगम एवं पारदर्शी सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। समूहों की सक्रिय भागीदारी से केंद्रों पर अनुशासन, समयबद्धता और व्यवस्था में भी सुधार देखा जा रहा है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में यह नवाचार जिले में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। प्रशासन द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी केंद्रों पर कार्य सुचारू रूप से संचालित हो और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उल्लेखनीय है कि इस पहल के माध्यम से शासन की मंशा के अनुरूप 'आत्मनिर्भर समूह, सशक्त किसान' की अवधारणा को साकार किया जा रहा है। आने वाले समय में यह मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकता है, जहां सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से शासकीय कार्यों को प्रभावी बनाया जा सके।

1कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने नटेरन एवं ताज खजुरी का किया निरीक्षण, विभिन्न शासकीय सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी

विदिशा,(निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज नटेरन विकासखंड मुख्यालय सहित ग्राम ताज खजुरी का भ्रमण कर विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, छात्रावास, आंगनबाड़ी केंद्र, उपार्जन केंद्र, उचित मूल्य दुकान एवं खाद विक्रय केंद्रों के माध्यम से आमजन को प्रदान की जा रही सुविधाओं का गहनता से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने शासकीय स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था एवं शैक्षणिक गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपलब्ध दवाइयों, स्टाफ की उपस्थिति एवं मरीजों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। छात्रावास एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार, स्वच्छता एवं अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया तथा आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर गेहूं खरीदी की व्यवस्था, किसानों की सुविधा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उचित मूल्य दुकानों एवं खाद विक्रय केंद्रों पर भी उन्होंने स्टॉक, वितरण प्रणाली एवं पात्र हितग्राहियों को मिल रही सामग्री की जांच की। कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर और प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जमीनी स्तर पर कार्य सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर कदम – अपर संचालक

विद्यार्थियों को दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा

नर्मदापुरम,(निप्र)। बदलते समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अब शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाने की दिशा में अग्रसर है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम राज्य के लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य को नई दिशा दे रहा है। शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के अपर संचालक एवं संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण नर्मदापुरम श्री मनीष वर्मा ने बताया कि सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि स्कूल स्तर से ही विद्यार्थियों को कौशलयुक्त बनाया जाए, ताकि वे केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बन सकें। उन्होंने कहा कि कक्षा 9वीं से ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, जिससे 12वीं तक पहुंचते-पहुंचते उनके पास एक मजबूत कौशल विकसित हो सके।

उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 तक प्रदेश के कुल 3367 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा लागू की जा चुकी है। इनमें 3138 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 22 प्रकार के व्यावसायिक ट्रेड संचालित हो रहे हैं, जबकि 229 हाई स्कूलों में एक-एक ट्रेड संचालित किया जा रहा है। इन स्कूलों में 2629 समग्र शिक्षा अभियान, 648 पीएम श्री योजना तथा 90 स्कूल स्टार स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत हैं। वर्तमान में राज्य के 5,95,546 छात्र-छात्राएं विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड एवं जॉब रोल में नामांकित हैं।

श्री वर्मा ने बताया कि कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर 9वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यह जानना आवश्यक है कि उनके विद्यालय में कौन-कौन से व्यावसायिक ट्रेड उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार उन्हें ट्रेड चयन की सुविधा प्रदान की जाती है। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यालय स्तर से ही कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

उन्होंने इसके प्रमुख लाभ बताते हुए कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, जिससे 12वीं के बाद सीधे रोजगार पाने की क्षमता विकसित होती है और स्वरोजगार शुरू करने का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह कार्यक्रम 17 सेक्टर स्किल काउंसिल से जुड़ा हुआ है तथा ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।

अंत में उन्होंने कहा कि लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश का प्रत्येक शासकीय विद्यालय एक 'स्किल हब' के रूप में विकसित हो। विद्यालय केवल डिग्री देने का माध्यम न रहकर जीवन कौशल प्रदान करने का केंद्र बने। इसके लिए विभाग एनएसडीसी, सेक्टर स्किल काउंसिल एवं उद्योग जगत के साथ सतत समन्वय स्थापित कर रहा है।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने गेहूँ उपार्जन केन्द्रों का किया आकस्मिक निरीक्षण, किसानों से भी की चर्चा

रायसेन,(निप्र)। जिले में बनाए गए विभिन्न उपार्जन केन्द्रों पर शासन के निर्देशानुसार गेहूँ उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा स्वयं जिले में विभिन्न उपार्जन केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर उपार्जन कार्य और केन्द्रों पर किसानों की सुविधा हेतु की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही सभी एसडीएम द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में उपार्जन केन्द्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

बुधवार को कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा गेहूँ उपार्जन केन्द्र देवनगर स्थित शिव वेयरहाउस बिसनखेड़ा, उपार्जन केन्द्र एक्सप्रेस वेयरहाउस गैरतपुर, पारसनाथ वेयरहाउस जमुनिया, आदर्श वेयरहाउस गैरतगंज, देवज्योति वेयरहाउस केसली, श्री हीरा वेयरहाउस तथा एचएस वेयरहाउस बाबई सहित अन्य उपार्जन केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने उपार्जन प्रक्रिया, उपज की तुलाई, गुणवत्ता आदि का जायजा लिया तथा उपस्थित अधिकारियों और केन्द्र प्रभारी से अभी तक उपार्जित गेहूँ की मात्रा की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि शासन की उपार्जन नीति के अनुरूप ही उपार्जन कार्य सम्पादित किया जाए।

साथ ही उपज विक्रय हेतु आए किसानों के लिए छायादार बैठक व्यवस्था, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने उपज विक्रय हेतु आए किसानों से भी उपज विक्रय हेतु स्लॉट बुकिंग सुगमता से होने, उपार्जन प्रक्रिया में लगने वाला समय और केन्द्रों पर की गई व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। निरीक्षण के दौरान सहकारिता, कृषि सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम हेतु कलेक्ट्रेट में 7 दिवसीय कंट्रोल रूम सक्रिय

विदिशा,(निप्र)। अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में कलेक्ट्रेट कार्यालय में 7 दिवसीय विशेष कंट्रोल रूम संचालित किया जा रहा है, जो 24 घंटे प्रभावशील रहेगा। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम कलेक्टर कार्यालय के एकीकृत कंट्रोल रूम के कक्ष क्रमांक 225 में 16 अप्रैल 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक संचालित रहेगा। आमजन बाल विवाह की सूचना मोबाइल नंबर 6269108974 पर दे सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के श्री अनुज जैन (मो. 8109527228) को इस कंट्रोल रूम का प्रभारी नियुक्त किया गया है। सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्टवार निर्धारित की गई है। प्रशासन द्वारा परियोजना स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां संबंधित परियोजना अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है। इनके संपर्क नंबर जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। परियोजना स्तर के प्रमुख संपर्क अधिकारी इस प्रकार हैं: श्री बी.पी. सिंह (गंजबासौदा-01) - 9425245237 श्री परितोष सोनकर (गंजबासौदा-02) - 9560926553 श्रीमती कृतिका व्यास (विदिशा ग्रामीण) - 7987156575 श्री अरुण कांत प्रजापति (ग्यारसपुर) - 8770109660 श्री ए.डी. डंगवाल (नटेरन) - 9827332534 श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव (कुरवाई) - 9340517261 श्री आयुष अग्रवाल (सिरोंज) - 9131386317 श्रीमती कालोदिया तिर्की (लटेरी) - 7697313318 श्रीमती नेहा रघुवंशी (विदिशा शहरी) - 6265341716 इन सभी नंबरों पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कंट्रोल रूम में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित क्षेत्र के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को तत्काल सूचित किया जाएगा तथा मौके पर पहुंचकर बाल विवाह को रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

दूरस्थ ग्राम गदाखार पहुंचकर कलेक्टर डॉ सोनवणे ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने पंचायत को सख्त निर्देश

बैतूल,(निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बुधवार को भीमपुर के दूरस्थ ग्राम गदाखार का भ्रमण कर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों से नल-जल योजना, आंगनवाड़ी केंद्र संचालन, पोषण आहार वितरण, स्वास्थ्य जांच एवं स्कूल व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अक्षत जैन एवं एसडीएम श्री अजीत मरावी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने पंचायत के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में जल स्तर नीचे जा रहा है, वहां वाटर रिचार्ज के कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पोषण ट्रैकर एप की मौके पर जांच कराई, जिसमें नव धात्री माताओं का पंजीयन अपूर्ण पाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी धात्री माताओं का समय पर पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें नियमित रूप से पोषण आहार मिल सके। साथ ही सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर को ऐप की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम में संचालित 'एक बगिया मां के नाम 'कार्य का स्थल निरीक्षण कर जलकुंड, पौधरोपण एवं नाडेप की गुणवत्ता का जायजा लिया।

तहसील कार्यालय में लापरवाही पर रीडर को नोटिस : भीमपुर स्थित नवीन तहसील

कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा एवं अभिलेख दुरुस्ती जैसे राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। प्रकरणों के निराकरण में देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने तहसीलदार रीडर को नोटिस देने के निर्देश दिए। साथ ही सभी प्रकरणों का समयसीमा में प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खरीदी केंद्र पर गेहूं की गुणवत्ता जांची : कलेक्टर डॉ सोनवणे ने बालाजी वेयरहाउस भीमपुर स्थित खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर गेहूं की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्धारित मानकों के अनुरूप ही उपार्जन एवं भंडारण किया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

आदर्श ग्राम पिपरिया में नल-जल व्यवस्था की समीक्षा : कलेक्टर ने आदर्श ग्राम पिपरिया का भी भ्रमण कर ग्रामीणों से नल-जल योजना की जानकारी ली। उन्होंने पंचायत सचिव को निर्देशित किया कि पानी संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए और पर्याप्त संसाधनों के बावजूद योजना बंद रहने जैसी स्थित निर्मित न हो।

जनगणना प्रशिक्षण का किया निरीक्षण : सांदीपनी स्कूल भीमपुर में आयोजित जनगणना प्रशिक्षण का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर डॉ सोनवणे ने प्रगणकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के समग्र विकास की आधारशिला है, इसलिए सभी बारीकियों को समझते हुए कार्य पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ किया जाए।

नारी शक्ति वंदन पखवाड़ाः छात्राओं में नेतृत्व, आत्मरक्षा और सशक्तिकरण का संचार

विदिशा,(निप्र)। राजमाता विजया राजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा में मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग एवं कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार 10 से 25 अप्रैल तक 'नारी शक्ति वंदन' पखवाड़ा उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. बी.डी अहिरवार के मार्गदर्शन में आयोजित इस पखवाड़े के अंतर्गत छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में शासकीय आदर्श महाविद्यालय जाफरखेड़ी की शिक्षाविद् डॉ. अनीता शाक्य द्वारा 'नारी शिक्षा के विभिन्न आयाम' विषय पर व्याख्यान दिया गया, जिससे छात्राओं को शिक्षा के महत्व और अवसरों की गहन जानकारी प्राप्त हुई। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से नारी सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं आत्मरक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय ब्लैक गोल्ड बेल्ट खिलाड़ी श्रीमती सोनम ठाकुर द्वारा जूडो-कराते का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए स्वयं की सुरक्षा का संकल्प भी दिलाया गया। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल सुरक्षा तथा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कार्यरत श्रीमती मीनाक्षी ठाकुर ने छात्राओं को कार्यस्थल पर लैंगिक समानता एवं महिला सुरक्षा विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. नीता पांडे ने नारी शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का सफल संयोजन एवं संचालन डॉ. विनीता प्रजापति द्वारा किया गया। मेंटल हेल्थ क्लब की प्रभारी प्रो. नीतू दांगी ने आयोजन में विशेष सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर प्रो. नीता दीक्षित, डॉ. मनोज अहिरवार, श्रीमती अदिति तिवारी, शकुन अहिरवार सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

कलेक्टर ने प्रशिक्षणार्थियों के साथ बैठकर जनगणना क्रियान्वित बिन्दुओ को जाना

विदिशा,(निप्र)। जनगणना-2027 के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री अंशुल गुप्ता ने प्रशिक्षणार्थियों के साथ बैठकर जनगणना कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की खासकर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दी जा रही जानकारी को बारीकी से परीक्षण किया है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने प्रशिक्षणार्थियों से सीधे संवाद करते हुए स्व-गणना प्रक्रिया, आंकड़ों की शुद्धता, समय-सीमा के पालन एवं फील्ड स्तर पर आने वाली संभावित चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसमें प्रत्येक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक की भूमिका अहम होती है।

जिले में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्व-गणना (ैमर्सि म्दनउमतंजपवद) की प्रक्रिया संचालित की जाएगी, जिसके अंतर्गत नागरिक स्वयं अपने परिवार से संबंधित जानकारी ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इसके पश्चात 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण (भ्वनेम स्पेजपदह) का कार्य किया जाएगा। उक्त कार्यों के सफल संपादन हेतु चार्ज स्तर के प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए नटेरन स्थित संदीपनी हाई स्कूल में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण में जनगणना से संबंधित तकनीकी पहलुओं, प्रपत्रों के सही भराव, मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग तथा फील्ड कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी जा रही है।

प्रशासन ने सभी प्रशिक्षणार्थियों से अपेक्षा की है कि वे प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान का प्रभावी उपयोग करते हुए जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न करें, जिससे जिले की सटीक एवं विश्वसनीय जनसंख्या आंकड़े तैयार हो।

अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने राधास्वामी वेयरहाउस गेहूं उपार्जन केंद्र का किया निरीक्षण

विदिशा,(निप्र)। अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने आज राधास्वामी वेयरहाउस स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने समर्थन मूल्य पर हो रहे गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया, किसानों की सुविधाओं तथा केंद्र पर उपलब्ध व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की।

अपर कलेक्टर श्री डामोर ने केंद्र पर किसानों के पंजीयन, स्लॉट बुकिंग, तौल व्यवस्था, गुणवत्ता परीक्षण एवं भंडारण व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थित किसानों से चर्चा कर उपार्जन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं की जानकारी ली और उनके त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्र पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए छाया, पेयजल, बैठने की व्यवस्था तथा समय पर तौल सुनिश्चित की जाए। साथ ही गेहूं की गुणवत्ता परीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं नियमानुसार संचालित करने पर जोर दिया।

अपर कलेक्टर ने वेयरहाउस में भंडारित गेहूं की सुरक्षा एवं रख-रखाव की स्थिति का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुसार किसानों को सुगम एवं पारदर्शी उपार्जन व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

शासन के निर्देशों के अनुरूप ही हो समर्थन मूल्य पर खरीदी

परिवहन और उठाव व्यवस्था में निरंतरता बनी रहे : कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा

कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिला उपार्जन समिति की बैठक के दौरान दिए महत्वपूर्ण निर्देश

नर्मदापुरम,(निप्र)।10:55 ढ्ढस्स्न

कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने जिले में संचालित गेहूं उपार्जन कार्य को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी आवश्यक दिशा-निर्देश उपार्जन कार्य में संलग्न प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी तक क्रमवार विस्तारपूर्वक प्रसारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी व्यवस्थाएं सुचारू एवं चाक-चौबंद रहें, यह सुनिश्चित किया जाए।

जिला उपार्जन समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिए कि उपार्जन के दौरान प्रत्येक विकासखंड में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त न हो। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर स्लॉट बुकिंग तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं आई जानकारी एसएमएस के माध्यम से मिलती रहे।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मद्देनजर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अचानक मौसम परिवर्तन की स्थिति में उपार्जित गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल, शेड तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि उपार्जित स्कंध का नियमित परिवहन निरंतर जारी रखा जाए। उठाव के लिए अनुबंधित परिवहन फर्म के पास उपलब्ध वाहनों की संख्या का आकलन किया जाए तथा उनके नियमित रोटेशन की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर की जा रही खरीदी में गेहूं की तुलाई, उठाव एवं स्टैकिंग के लिए हम्मालों एवं अन्य संसाधनों की किसी भी प्रकार की कमी न हो। साथ ही किसानों को उपज विक्रय के पश्चात भुगतान समय पर और शीघ्रता से किया जाए, इसके लिए जिला एवं खंड स्तरीय समितियां नियमित निगरानी करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी उपार्जन केंद्रों पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही खरीदी की जाए तथा केवल एफएक्यू (उचित औसत गुणवत्ता) स्तर के गेहूं का ही उपार्जन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान डिप्टी कलेक्टर तथा प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती नीता कोरी, उपसंचालक कृषि श्री रविकांत सिंह, डीआरसीएस श्री शिवम मिश्रा सहित जिला उपार्जन समिति के अन्य सदस्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दोनों हाथ शिथिल, पैरों से लिख 12वीं में किया टॉप

छात्रा द्रोपदी का सम्मान करने खुद गईं थी कलेक्टर, पिता हैं मजदूर

मंडला (नप्र)। हाल ही में मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित किया गया है। छात्रा द्रौपदी ने पैरों से लिखकर 65 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। करीब दो साल पहले छात्रा द्रोपदी ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पैरों से लिखकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उस दौरान मंडला की तत्कालीन कलेक्टर डॉ सलोनी सिडाना खुद छात्रा से मुलाकात करने के लिए उसके गांव गईं थीं और उसे पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया था।

तत्कालीन कलेक्टर ने द्रोपदी का सम्मान किया था और उसका उत्साहवर्धन भी किया था। कलेक्टर से मिलने के बाद द्रौपदी ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसले किया था। उस समय द्रौपदी ने कलेक्टर से कहा था कि वह आगे पढ़ाई करेगी और भविष्य में एक अफसर बनकर समाज की सेवा करेगी।

जन्म से शिथिल हैं दोनों हाथ- द्रौपदी भीमडोगरी स्कूल की छात्रा है। 12वीं की परीक्षा में 65 प्रतिशत अंक हासिल कर उसने सबको हैरान कर दिया है। जन्म से दोनों हाथों के शिथिल होने के कारण द्रोपदी पैरों से लिखती है, लेकिन उसके हौसले किसी भी बाधा से कहीं ऊंचे हैं। छात्रा के परिजनों ने भी बेटी की कुशलता को देखने हुए उसकी पढ़ाई आगे जारी रखने का फैसला किया।

पैरों से लिखने की शुरुआत की- द्रौपदी धुर्वे मवई विकासखंड के करौंदा टोला की रहने वाली है। छात्रा दोनों हाथ से दिव्यांग है। बावजूद इसके उसके जज्बे से उसका अध्ययन जारी हैं। वह अपने पैरों में पेन फंसाकर लिखती है। छात्रा के दोनों हाथ जन्म से ही शिथिल हैं।

सिंगरौली में बैंक रॉबरी

5 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 35 लाख लूटे

सिंगरौली (नप्र)। सिंगरौली में बैंक रॉबरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शुक्रवार दोपहर को 5 हथियार बंद बदमाशों ने घुसकर जमकर उत्पात मचाया। पूरे बैंक को बंधक बना लिया और मैनेजर को बंदूक की बट से मारकर घायल कर नकदी से भरी पेटी और कैश कलेक्शन काउंटर को लूट लिया। लुटेरे नकदी सहित सोना–चांदी सहित करीब 35 लाख की लूट करके बड़े आराम से निकल गए।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सिंगरौली के बैढ़न क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच में रोजमर्रा की तरह काम चल रहा था। दोपहर करीब एक बजे दो बदमाश हथियार लेकर बैंक में घुसते हैं। एक बदमाश ने सिर पर हेलमेट लगा रखा था। उन्होंने हथियार लहराते हुए लोगों को चुप रहने के लिए बोला और सीधे मैनेजर को पकड़ लिया। इसी दौरान पीछे से तीन और हथियार बंद बदमाश बैंक के अंदर आ गए। सभी ने बैंक में जमकर धमकाया, उत्पात मचाया। चंद मिनटों में वे लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर भाग गए।

बैंक मैनेजर पर बट से हमला, चाबियां छीनने के लिए मारपीट- पुलिस के अनुसार बदमाशों ने पूरे बैंक को बंधक बनाया था। पहले आए दो बदमाशों ने बैंक मैनेजर सहित कर्मचारियों पर बंदूक तान दी थी। बाद में आए तीन और बदमाशों ने ग्राहकों व अन्य कर्मचारियों को भी बंदूक की दम पर बंधक बना लिया। पुलिस के अनुसार मैनेजर ने जब कैश रूम की चाबी देने से इंकार किया तो एक बदमाश ने उसके सिर पर बट दे मारा। उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया।

नकदी से भरी पेटी, कैश काउंटर लूट ले गए- जानकारी अनुसार बदमाश करीब 20 मिनट तक बैंक के अंदर रहे, उन्होंने बैंक से नकदी से भरी पेटी, कैश काउंटर का कलेक्टशन, सोना-चांदी लूट लिया और फरार हो गया। बैंक से करीब 30 से 35 लाख रुपए की लूट होना बताया जा रहा है। घटना के समय बैंक के गेट या अंदर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। लुटेरे भागते समय बैंक के अपोजिट साइड में सड़क के दूसरी तरफ एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं।

पुलिस अधिकारी, सिंगरौली ने बताया दोपहर में बैंक आफ महाराष्ट्र में लूट की वारदात हुई है। हथियारबंद लुटेरे करीब 14.50 लाख रुपए सहित आज का कलेक्शन ले गए। सोना-चांदी भी है। मामले में जांच की जा रही है

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल सहित एसपी मनीष खत्री भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने तत्काल शहर के सभी बाहरी की ओर जाने वाले मार्गों को सील कर दिया।

भोपाल की बेटी ने रचा इतिहास

56 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो फतह

भोपाल। अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय की मिसाल पेश करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल में सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत सुनीता सिंह ने अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक तिरंगा और स्टेट बैंक का झंडा फहराया।

56 वर्ष 5 माह की आयु में 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने 5 हजार 895 मीटर ऊँची इस चोटी को फतह कर सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनने का गौरव हासिल किया। शिखर पर पहुँचकर उन्होंने बैंक और देश का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों, मौसम, उम्र और कामकाजी व्यस्तता के बाद भी यहां तक पहुंचना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब इस सफलता से उत्साहित होकर वे और नए लक्ष्य हासिल करना चाहती हैं।

अपने पर्वतारोहण से जुड़े अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया, बैंकिंग की व्यस्त नौकरी के साथ पर्वतारोहण के सपने को पूरा करना आसान नहीं था। इस उम्र में प्रशिक्षण और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना सभी के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन बैंक के अनुशासन और सेवा के संस्कारों ने मुझे यह हिम्मत दी। स्टेट बैंक के सहकर्मियों ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे कामकाजी महिलाओं और पेशेवरों के लिए प्रेरणा बताया है। सुनीता सिंह की इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि उम्र और नौकरी, सपनों की राह में बाधा नहीं बनते। पर्वतारोही सुनीता सिंह ने इससे पहले यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भी तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया था । सुनीता ने 24 अगस्त 2025 को इस 18,510 फीट ऊंचे इस शिखर को फतह किया था । सुनीता सिंह ने जबलपुर की हैं और उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से हासिल की है।

भोपाल में कमर्शियल गैस को लेकर नई व्यवस्था ; 2 सिलेंडर मिलेंगे

जिन घरों में शादी, उन्हें देना होगा शादी का कार्ड

भोपाल (नप्र)। भोपाल में शादी सीजन शुरू होते ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब जिन घरों में शादी है, उन्हें पास की गैस एजेंसी पर शादी का कार्ड जमा कराना होगा। इसके बाद ही अधिकतम दो कमर्शियल सिलेंडर दिए जाएंगे।

प्रत्येक सिलेंडर के लिए 2200 रुपए डिपॉजिट देना होगा। दो सिलेंडर के लिए कुल 4400 रुपए जमा कराए जाएंगे, जो इस्तेमाल के बाद सिलेंडर लौटाने पर वापस कर दिए जाएंगे। हालांकि, गैस भरवाने का शुल्क अलग से 1850 रुपए प्रति सिलेंडर देना होगा। सिलेंडर 2 से 3 दिन के भीतर एजेंसी पर लौटाना अनिवार्य रहेगा।

कंपनियों से चर्चा के बाद व्यवस्था- भोपाल के फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया कि सभी एलपीजी कंपनियों के अधिकारियों से चर्चा के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए शादी का कार्ड, पहचान पत्र और एक आवेदन देना होगा, जिसमें शादी की तारीख, समय और स्थान की जानकारी देनी होगी।

डॉ. भार्गव राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान से अलंकृत

नई दिल्ली। रिटायर्ड आईएएस, मोटिवेशनल स्पीकर अशोक भार्गव को नई दिल्ली में हयात होटल में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रीय उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉ भार्गव को यह प्रतिष्ठित सम्मान मुख्य अतिथि क्रिकेटर मदनलाल एवं कैमरून गणराज्य की उच्चायुक्त सुश्री सिलवी मिशेल मपोन टिएक मांबो द्वारा प्रदान किया गया। डॉ भार्गव को यह अवार्ड उनके द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, कोविद नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण, सर्वोत्तम निर्वाचन प्रक्रिया, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, उत्तरदायी और संवेदनशील सुशासन, स्वतंत्र लेखन एवं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्रभाषा हिंदी तथा नागरी लिपि के विकास आदि के क्षेत्र में स्थापित किए गए उल्लेखनीय कीर्तिमानों के लिए प्रदत्त किया गया है।

प्रदेश में 43 डिग्री की झुलसाती गर्मी में लग रहे स्कूल

बच्चे बोले-अब तो छुट्टी करा दीजिए सीएम अंकल ; 20 जिलों में आज लू की चेतावनी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में सूरज के तेवर तल्ख हो चुके हैं। पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। आसमान से बरसती इस आग के बीच बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं, जिससे उनका हाल बेहाल है। चिलचिलाती धूप और पसीने से तर-बतर बच्चे अब एक ही मांग कर रहे हैं- सीएम अंकल, बहुत गर्मी है, अब तो छुट्टियां कर दीजिए ! मौसम विभाग ने आज 20 जिलों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। हालांकि, कुछ जिलों में स्कूलों का समय बदला गया है। रायसेन और अनूपपुर में स्कूलों का समय सुबह 7.30 से दोपहर 12 तक कर दिया गया है। डिंडौरी में भी नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूल सुबह साढ़े 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही लगाए जाएंगे। मैहर में भी कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। यहां अब नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही लगेंगे।

नर्मदापुरम में 43 डिग्री, रतलाम में 42 डिग्री तापमान- गुरुवार को नर्मदापुरम का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सीजन का सबसे ज्यादा है। वहीं, रतलाम, धार, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में लू जैसे हालात रहे। नर्मदापुरम के बाद रतलाम दूसरा सबसे गर्म शहर रहा, यहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री दर्ज किया गया।

दमोह-मंडला में 42 डिग्री, शाजापुर में 41.8 डिग्री, गुना में 41.7 डिग्री, मलाजखंड, टीकमगढ़-छिंदवाड़ा में 41.5 डिग्री, उमरिया-श्योपुर में 41.4 डिग्री, धार-खजुराहो में 41 डिग्री, सतना में 40.9 डिग्री, खरगोन में 40.8 डिग्री, सागर में 40.7 डिग्री, दतिया-सीधी में 40.6 डिग्री, खंडवा-बैतूल में 40.5 डिग्री, सिवनी-रीवा में 40.4 डिग्री और नौगांव में पारा 40.2 डिग्री सेल्सियस पारा रहा।

नर्मदापुरम में भीषण गर्मी, स्कूलों का समय बदला- नर्मदापुरम में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। बढ़ते तापमान के कारण छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब जिले के सभी शासकीय और निजी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही संचालित होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, ताकि गर्मी के बीच विद्यार्थियों को राहत मिल सके।

ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 महिलाओं की मौत, 26 घायल

श्योपुर से 4 ग्वालियर रेफर, कई गंभीर, मदद के लिए चीखते-चिल्लाते रहे लोग

श्योपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में गुरुवार रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है।हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। मामला विजयपुर थाना क्षेत्र के खितरपाल गांव का है। जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान सरोज गुर्जर, सुनैना गुर्जर, सीमा गुर्जर और गीता राव के रूप में हुई है। ट्रैक्टर से बीरपुर थाना क्षेत्र के घूंघस गांव से विजयपुर थाना क्षेत्र के झारबडौदा गांव भात मांगने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे ।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला

ट्रॉली के अंदर ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। विजयपुर से 3 किलोमीटर पहले खितरपाल गांव के पास ट्रैक्टर अनबैलेंस हो गया। इससे ट्रॉली पलट गई। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया।

पलटी हुई ट्रॉली को हाथों से सीधा किया

घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद लोगों ने क्रेन का इंतजार नहीं किया। हाथों से ही पलटी हुई ट्रॉली को सीधा किया। इससे मृतकों और घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों को घटनास्थल पर मौजूद गाड़ियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री रामनिवास रावत

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। पूर्व वनमंत्री रामनिवास रावत, एसडीएम अभिषेक मिश्रा और टीआई राजन गुर्जर सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे। राहत और बचाव कार्य की निगरानी करते रहे। एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने बताया कि हादसे के बाद पांच लोगों की हालत गंभीर है। चार लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है, जबकि एक व्यक्ति का इलाज विजयपुर के सिविल अस्पताल में चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने दु :ख व्यक्त कर मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के खितरपाल गांव में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से महिलाओं के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मृतकों के परिजन को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए एवं अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दुर्घटना में जो घायल हुए हैं, उनको उपचार प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की भी कामना की।